लखनऊ

बुधवार, 22 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 324

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। — स्वामी विवेकानंद

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

आसाराम की सेहत की स्थिति का आकलन करेगा मेडिकल बोर्ड, अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को निर्देश दिया कि वह स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें। आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 मई को वर्ष 2013 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 80 वर्षीय आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मेडिकल बोर्ड को एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ तीन महीने पहले ही आसाराम ने काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्राएं की थीं। मेहता ने कहा, उसे इस आधार पर जमानत मिली थी कि वह लगभग निष्क्रिय अवस्था में हैं। लेकिन अब वह घूम रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा, हम नियमित जमानत नहीं दे रहे हैं। अगर हमें यह संतोष होगा कि मेडिकल आधार पर इसकी जरूरत है, तभी विचार करेंगे। पहले मेडिकल रिपोर्ट आने दीजिए। आसाराम की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले को एम्स के निदेशक के पास भेजा जाए, ताकि वह डॉक्टरों की एक टीम बनाकर आसाराम की पूरी मेडिकल जांच करा सकें। उन्होंने कहा कि इसके बाद डॉक्टर यह रिपोर्ट दे सकते हैं कि आसाराम को मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है या नहीं।

5 साल, 93 मौतें... नीट के दबाव पर रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में नीट को लेकर चल रहा विवाद अब सिर्फ पेपर लीक या परीक्षा में कथित गड़बड़ियों तक सीमित नहीं रह गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP और छात्र संगठनों के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन ने इस बहस को एक नए मोड़ पर ला दिया है। प्रदर्शनकारी सिर्फ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग नहीं कर रहे, बल्कि छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को भी बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इसी बीच आई एक रिपोर्ट ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। मेडिकल डायलॉग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच सालों में नीट से जुड़े दबाव के बीच 93 छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इनमें साल 2026 में अब तक 14 मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं, जब कई राज्यों में छात्र परीक्षा प्रणाली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कोचिंग के दबाव और बार-बार होने वाले विवादों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले इस बात की ओर जरूर इशारा करते हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ा मानसिक दबाव एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों नीट को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। CJP और कई छात्र संगठन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं।

नीट अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी

'आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, दोषियों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई'

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में धांधली और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। मंगलवार को एनडीए (NDA) संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कहा कि NEET परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। NDA की 'मंगल मिशन' बैठक में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

NDA बैठक में नेताओं को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने कहा कि सरकार किसी भी गड़बड़ी के कारण छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, 'हम छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे।' प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि NEET परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। 'NEET में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भेजा जाएगा।'

नीट मामले में दलगत राजनीति नहीं हो

आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए. ये सिर्फ एक राज्य नहीं पूरे देश का मामला है. इस मामले में दलगत राजनीति नहीं होना चाहिए. इसके अलावा फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा हुई. पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखा जाएगा. कोई नुकसान नहीं होने देंगे. रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने मार्गदर्शन दिया, देश ने पिछले महीनों में जो सफलता हासिल की उसका जिक्र किया.

'राष्ट्रीय चिंता का विषय, न हो राजनीति' राजनीति

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों से भी अपील की कि जहाँ कहीं भी ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आएं, वहां बिना किसी ढिलाई के त्वरित व सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि योग्य उम्मीदवारों का समय और भविष्य प्रभावित न हो, इसके लिए पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा (Re-exam) आयोजित कर परिणाम भी समय पर घोषित किए गए।

'पीएम मोदी माफी मांगें और इस्तीफा दें, अमित शाह भी पद छोड़ें', राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों पर कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने छात्रों के खिलाफ सोमवार को हुई कार्रवाई को लेकर सदन में चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में पहुंचा और अपनी मांग रखी। इस दौरान समाजवादी पार्टी (सपा), वाम दलों, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा छात्रों की पिटाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी त्यागपत्र देना चाहिए। इससे पहले, उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने बिरला से मुलाकात कर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने का अनुरोध किया था, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा के लिए उन्हें सरकार से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "दूसरे शब्दों में, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि संसद में बहस कराने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति चाहिए।

'लोकतंत्र की जननी' बच्चों पर लाठी नहीं चलाती

इंडिया ब्लॉक की बैठक में बोले खरगे, पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडिया ब्लॉक के नेता मंगलवार सुबह नई दिल्ली स्थित संसद भवन में एक अहम रणनीति बैठक हुए। ताकि वे अपने संयुक्त दृष्टिकोण का समन्वय कर सकें। इसके साथ ही मानसून सत्र की कार्यवाही से पहले सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सकें।

मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष के समन्वय को तेज करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा, वामपंथी और शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टियों के सदस्यों सहित इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने संसद भवन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के साथ एक औपचारिक बैठक की।

पुलिस की कार्रवाई की निंदा

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए घोषणा की। उन्होंने अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही न्याय की मांग कर रहे युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की है। मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रशासनिक कार्रवाई पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'कल देश ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और सरकार की ओर से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचलते हुए देखा। न्याय की मांग कर रहे छात्रों की आवाजों को जवाब देने के बजाय बल प्रयोग से दबा दिया गया। 'लोकतंत्र की जननी' अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। इन दुखद परिस्थितियों में, मैंने आज अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और हर उस नागरिक का मैं तहे दिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं। आपका स्नेह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज जश्न मनाने का दिन नहीं है। आज जवाबदेही तय करने का दिन है। लोकतंत्र को बहाल करो।'

खरगे ने आगे कहा 'न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर क्रूर लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया? संसद को लगभग सील क्यों कर दिया गया और इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? बार-बार पेपर लीक होने और लाखों युवाओं की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा?' मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा, 'सरकार को संसद में इस मुद्दे पर तुरंत पूर्ण चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। 21वीं सदी की छात्र-

जंतर-मंतर पर सीजेपी का फिर हल्लाबोल! संसद जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा कड़ी, 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

नई दिल्ली, एजेंसी। सोमवार को 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई भारी हिंसा और पुलिस के साथ तीखी झड़प के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मंगलवार (21 जुलाई) को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है। देर रात प्रदर्शनकारियों के जुटने पर पुलिस ने उन्हें वापस आने से नहीं रोका और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने साफ़ चेतावनी दी है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबरों के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वापस आने से नहीं रोका और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाज़त होगी। हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी फैलाने या कानून-व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

CJP, परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक ज़मीनी आंदोलन है। इसकी शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी से हुई थी जिसमें उन्होंने युवाओं को 'कॉकरोच' कहा था। यह समूह 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और वामपंथी संगठन AISA से जुड़े छात्रों के भूख हड़ताल में शामिल होने के बाद इस विरोध प्रदर्शन को और तेज़ी मिली। जहां प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर फिर से अपना मंच बना लिया है, वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए हैं, खासकर संसद की ओर जाने वाले रास्तों पर। जंतर-मंतर के आस-पास की सड़कें खुली हैं, लेकिन अहम जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि आशंका है कि प्रदर्शनकारी संसद की ओर एक और मार्च करने की कोशिश कर सकते हैं। कई विपक्षी नेताओं के भी विरोध स्थल पर आने की उम्मीद है, इसलिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने सोमवार के विरोध मार्च के दौरान हुई हिंसा और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई। X पर एक पोस्ट में, CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि नड्डा ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने बताया कि सरकार ने कोई पक्का वादा नहीं किया है और दोहराया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों में मतभेद, अब तीसरे जज करेंगे फैसला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की राय अलग-अलग आई है। उसके बाद, मामला तीसरे जज की बेंच को भेजा गया। मतभेद के चलते अब तीसरे न्यायाधीश की बेंच अंतिम सुनवाई और फैसला करेगी। बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट का यह मामला प्रदेशभर के लिए अहम माना जा रहा है। बता दें कि हमीरपुर के मामले में बुलडोजर कार्रवाई की वैधता पर खंडपीठ एकमत नहीं हो सकी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी का मकान नहीं गिराया जा सकता। एफआईआर के बाद सामान्य परिस्थितियों में दो वर्ष तक ध्वस्तीकरण न हो, सार्वजनिक भूमि खाली कराना अपवाद है। तीन वर्ष या उससे अधिक पुराने कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से पहले एक वर्ष का नोटिस देने की भी राय दी गयी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इन सुझावों से असहमति जताई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता है। 20 जुलाई को पारित एक अलग फैसले में, न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा: "नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन करने की आड़ में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के आवास को ध्वस्त करने की जल्दबाजी अनुचित है, यह कार्यकारी विवेक का प्रतिशोधात्मक प्रयोग है और इसलिए, एफआईआर दर्ज होने की तारीख से दो साल की अवधि तक उसके घर को ध्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।" जज ने यह भी कहा कि परेशान व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट जाने का रास्ता हमेशा खुला है। जस्टिस नंदन ने कहा, "मेरी राय में कोई तय समय नहीं रखा जा सकता, क्योंकि असल में, इससे उस समय के लिए कानून का काम रुक जाएगा।"

यूक्रेन में जहाज पर हमले में चार भारतीयों की मौत, भारत ने घटना की कड़ी निंदा की

नई दिल्ली, एजेंसी। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों सहित कुल 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और युद्ध के बीच वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, एम.वी. गोल्डन लियो नामक इस मालवाहक जहाज पर चालक दल के कुल 17 सदस्य सवार थे, जिनमें से पांच भारतीय नागरिक थे। यह हमला 19 जुलाई की शाम को उस समय हुआ जब जहाज बंदरगाह से आगे बढ़ रहा था। इस हमले में चार भारतीयों की जान चली गई, जबकि एक अन्य भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हमको लग रहा था कि भीड़ हम पर हमला कर देगी : कंगना रनौत

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के हालिया विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली पुलिस के रुख का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के समय स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि संसद के भीतर मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबराए हुए थे। सांसद कंगना रनौत ने संसद परिसर के अंदर का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा- संसद के अंदर हर कोई दहशत में था। संसद के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए थे और हम सांसद अंदर ही फंस कर रह गए थे। यहां तक कि सदन स्थगित होने के बाद भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उग्र भीड़ के रुख पर चिंता जताते हुए उन्होंने आगे कहा- आपने देखा होगा कि कैसे भीड़ हमला करने की कोशिश कर रही थी। एक वक्त तो हम सभी इस डर में थे कि वे कहीं हम पर हमला न कर दें। प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ और कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमारे लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह काम किया। गौरतलब है कि सोमवार को CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली थी। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग और लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेताओ ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया है। भाजपा का कहना है कि पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया, ताकि स्थिति को हिंसक होने से रोका जा सके।

'चलो संसद' मार्च के बाद एक्शन में सरकार, जेपी नड्डा ने आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारियों का जाना हाल

नई दिल्ली, एजेंसी। 'चलो संसद' मार्च के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मंगलवार को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों से मुलाकात कर घायलों के इलाज और उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने अस्पतालों में भर्ती प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बताया कि सभी घायल चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनका उपचार जारी है।

गौरतलब है कि सोमवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले आयोजित 'चलो संसद' मार्च में हजारों लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी, जिसमें कई लोग घायल हुए।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटनाक्रम में लगभग 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि 118 से अधिक पुलिसकर्मी, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, चोटिल हुए।

इससे पहले सोमवार को जेपी नड्डा ने CJP के दो प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। बैठक के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर आंतरिक स्तर पर विचार-विमर्श करेगी।

ज़रूरत पड़ी तो मैं दिल्ली जाऊँगी... सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का ममता ने दिया संकेत

नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह दिल्ली जाएंगी और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी। साथ ही, उन्होंने BJP के ख़िलाफ़ विपक्ष की एकजुटता का भी आह्वान किया। कोलकाता में TMC की 'शहीद दिवस' रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, 'हमने शुरू से ही सीजेपी का समर्थन किया है। अगर ज़रूरत पड़ी, तो मैं दिल्ली जाऊंगी और उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होऊंगी।

दिल्ली में सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन का ज़िक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि छात्रों के ख़िलाफ़ कथित पुलिस कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी मोड़ ली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा लोग बीजेपी के अत्याचारों को समझ सकते हैं। इसने हिटलर और स्टालिन को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने टीएमसी के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की और दावा किया कि सोमवार रात बंदूकें लिए हुए करीब 600 बाइक सवार 'शहीद दिवस' के मंच को नष्ट करने आए थे। उन्होंने कहा कल रात मैंने, अभिषेक और अन्य नेताओं ने बीजेपी के लगातार हमलों से 'शहीद दिवस' के मंच की सुरक्षा की।

आजम खां ने जिस अफसर को बताया था 'तनखैया', उसी के हाथ अब जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों का भविष्य

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर। सपा महासचिव आजम खां ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन अफसर आंजनेय कुमार सिंह को तनखैया (तनख्वाह पर काम करने वाला) कहते हुए उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। फिलहाल जौहर विश्वविद्यालय का भविष्य उन्हीं के भरोसे पर है।

रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के विश्वविद्यालय के 40 में से 38 अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील दायर की गई है। 28 जुलाई को इसपर सुनवाई होगी।

आजम को तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह (अब कमिश्नर) के खिलाफ टिप्पणी करने

के मामले में दो साल की सजा हो चुकी है। आरडीए उपाध्यक्ष व डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के बिना मानचित्र के बनाए जाने पर उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था।

इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को खुद ध्वस्त करने के लिए 20 दिन का समय दिया है। इसके बाद आरडीए खुद कार्रवाई करेगा और खर्चा विश्वविद्यालय प्रबंधन से वसूलेगा। सोमवार को विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता जुनैद एजाज ने मंडलायुक्त के न्यायालय में ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

15 पेज की अपील में तर्क है कि विश्वविद्यालय का क्षेत्र ग्राम सींगनखेड़ा भवन निर्माण के समय क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधीन था। उस समय उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 लागू था। क्षेत्र पंचायत से अनुमति का प्रविधान था, अनुमति न लेने पर अधिकतम 500 रुपये जुर्माने का प्रविधान था। आरडीए का गठन 27 सितंबर, 2024 को हुआ, जबकि विश्वविद्यालय के भवन 2018 में ही बन चुके थे। बाद में गठित प्राधिकरण पूर्व निर्मित भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं कर सकता।

भूमि उपयोग का तर्क आरडीए के नोटिस में स्वयं भूमि को शैक्षिक गतिविधियों के लिए चिन्हित बताया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में केवल शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसलिए भूमि उपयोग के आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उचित नहीं है।

हाई कोर्ट का भी विकल्प

सपा विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता कासिफ खां ने बताया कि मंडलायुक्त के न्यायालय में दाखिल की गई अपील पर सुनवाई के बाद अगर आरडीए का आदेश निरस्त कर दिया जाता है तब ये प्रकरण यहीं समाप्त हो जाएगा। अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है और आरडीए के आदेश को सही ठहराता है तो उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील करने का विकल्प है।

वर्षों से उपेक्षित है इसौली विधानसभा

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार सुल्तानपुर। वर्ष 2012 के परिसीमन बाद बनी इसौली विधानसभा विकास कार्यों के लिए उपेक्षा का शिकार हो रही है।आम जन से जुड़ी समस्याओं का कोई भी जन प्रतिनिधि निदान नहीं करवा पा रहा है। बता दे कि विगत वर्षों में बढ़ती जनसंख्या व आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय विकास खंड के बहलोलपुर गांव में 132 केवीए पावर हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव के बाद राजस्व विभाग ने जमीन उपलब्ध कराकर विद्युत विभाग को सौप दी। लेकिन आज तक उसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। सांसद मेनका गांधी के कार्यकाल में वर्ष 1998 में भाजपा कार्यकाल में स्थापित 33 केवी पावर हाउस का लोड कम करने के लिए सरकौड़ा पावर हाउस की स्थापना तो करा दी गई लेकिन 33 हजार की जो लाइन 400 पयागीपुर से आती है उसी से कुड़वार के साथ ही इसका भी संचालन शुरू हो गया। अन्ततः आए दिन ओवर लोड के चलते 33 हजार की लाइन फाल्ट में चली जाती है। जिसका खामियाजा विद्युत निविदा संविदा कर्मचारियों के साथ साथ लाखों आबादी को भुगतना पड़ता है।जिले से मात्र 12 किमी की दूर बसे ब्लॉक मुख्यालय कस्बे पर आए दिन बिजली की समस्या रहती है।साथ ही कस्बे की बात करे तो अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम की स्थिति रहती है।जिस पर कभी भी विभागीय अधिकारयों की नजर नहीं पड़ती है।विकास खंड क्षेत्र के ऊंचगांव में भी 33 केवीए पावर हाउस प्रस्तावित है लेकिन बस कागजों में। जमीन पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है।

घर में चल रही थी तेरहवीं, पंडित कर रहे थे भोजन, सासनी में अचानक भरभराकर गिरी मकान की छत

आर्यावर्त संवाददाता

हाथरस। सासनी कस्बे में लगातार हो रही बारिश के बीच छिपैटी मोहल्ले में मंगलवार को एक कमरे की छत भरभराकर गिर गई। हादसे के समय घर में त्रयोदशी संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था और ब्राह्मण भोज के बाद बाहर निकल रहे लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। छिपैटी निवासी रविंद्र कुमार का मकान अशोक कुमार किराये पर लेकर करीब 65 वर्षों से रह रहे हैं। बारिश के कारण जर्जर हो चुके मकान की एक कमरे की छत अचानक गिर गई। अशोक कुमार की पत्नी सरोज ने बताया कि उनके बेटे संतोष कुमार की मृत्यु के बाद त्रयोदशी संस्कार का आयोजन किया गया था। एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा।

विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 1450 किलो लहन नष्ट

ुल्तानपुर। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत मंगलवार को जिले में व्यापक कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं उप आबकारी आयुक्त, अयोध्या प्रभार के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र वर्मा के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम बल्लीपुर एवं चुनहा में दबिश दी। कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक रण विजय सिंह (क्षेत्र-1), अरुण कुमार (क्षेत्र-4) एवं नेहा श्रीवास्तव (क्षेत्र-5) सहित आबकारी विभाग के स्टाफ तथा कोतवाली नगर पुलिस की टीम शामिल रही। संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो आबकारी अभियोग पंजीकृत किए गए। टीम ने मौके से करीब 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की, जबकि लगभग 1450 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

डायरिया रोको अभियान का शुभारम्भ

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। डायरिया रोको अभियान (स्टॉप डायरिया कैम्पेन) का मंगलवार को विधिवत शुभारम्भ करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह ने जिला महिला चिकित्सालय से जागरूकता रैली को रवाना किया।

इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कर्मवीर सिंह ने हस्ताक्षर अभियान पर हस्ताक्षर कर कहा कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के लिए जनजागरूकता बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करेंगी और ओ.आर. एस. के पैकेट और जिंक की गोलियों का वितरण भी करेंगी। इसके साथ ही दस्त से प्रभावित बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को संदर्भित करेंगी।मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जिले

में 25 अगस्त तक चलने वाले डायरिया रोको अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू भी "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन और समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। ए एन एम टी सी की छात्राओं द्वारा महिला ओ.पी. डी. में रोल प्ले के माध्यम से डायरिया क्या है, कैसे फैलता है, ओ आर एस एस एवं जिंक का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में जागरूक किया।

इस मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक रघुबीर सिंह ने कहा कि डायरिया रोको अभियान के लिए ए. एन. एम और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों को अवगत कराएंगी कि बारिश और उमस में बच्चा डायरिया की चपेट में कई कारणों से आ सकता है, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, खुले में शौच करने या बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें। डायरिया का सही इलाज ओआरएस का घोल और जिंक की के टेबलेट हैं, जिन्हें उम्र के अनुसार 14 दिनों तक जरूर दें। उन्होंने कहा कि बच्चे को दिन भर में तीन या तीन से अधिक बार दस्त हो तो समझना चाहिए कि बच्चा डायरिया से ग्रसित है और ऐसे में उसको तत्काल ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए, साथ ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना चाहिए। साथ में सभी स्वास्थ केंद्रों पर ओआरएस कॉर्नर बनाने की बात भी की गई।

इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कर्मवीर सिंह, डॉ. विजय सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव, चीफ फार्मासिस्ट योगेश कुमार, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक चंद्रशेखर, अर्बन हेल्थ कॉर्डिनेटर प्रमोद कुमार, प्रधानाचार्य फिरोज बी, सीसीपीएम संतोष एवं लोकेश, पीएसआई इंडिया से कोमल घई, मोहम्मद रिजवान, ममता सैनी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

निर्माण कार्य रोकने को लेकर मारपीट

ुल्तानपुर। कुड़वार थाना क्षेत्र के ग्राम कटावां निवासी प्रार्थिनी कुशुम पत्नी सुशील ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मंगलवार सुबह करीब 8 बजे उनके दरवाजे के सामने हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के दौरान गांव के बल्लू सिंह पुत्र शीतला प्रसाद, भुल्लुर पुत्र रामलाल, मोनी पत्नी विजय कुमार तथा रमेश पुत्र शिवराम ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार घटना में कुशुम, ज्योति पत्नी भीम प्रकाश, नाबालिग रागिनी पुत्री सुशील और रोहित पुत्र सुशील घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराकर आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

गोरखपुर विवि में शोधार्थियों को मिलेगी सहूलियत, परीक्षा प्रारूप में भी होगा बदलाव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधार्थियों के हित में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि शोध के दौरान नौकरी मिलने वाले शोधार्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे उनका शोध कार्य बाधित न हो।

इसके लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश में उपलब्ध विशेष प्रावधानों का अध्ययन कर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए समिति गठित की जाएगी। समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र की परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव का निर्णय लिया गया। कुलपति ने बताया कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं मुख्य रूप

से वर्णनात्मक पद्धति से कराई जाएंगी। केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित मूल्यांकन के बजाय विद्यार्थियों की विषयगत समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को परखने वाले प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों और शोधार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध और मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीतियां विकसित कर रहा है। उन्होंने सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए।

29.44 करोड़ से सुदृढ़ होगा एनएच-128, विधायक ने किया भूमिपूजन

ुल्तानपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-128 के कटका-सौरमऊ सेक्शन के सुदृढ़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को कटका बाजार में करीब 29.44 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का भूमिपूजन सदर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया।भूमिपूजन के बाद विधायक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सड़क,पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी,वहीं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।कार्यक्रम में कटका मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, नंदन चतुर्वेदी, संतोष सिंह, प्रधान जमुना सिंह, प्रधान शंकर मिश्रा, प्रधान मोनू चतुर्वेदी, प्रधान मनीष तिवारी, प्रधान बबलू मिश्रा, मिंटू सिंह समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि,भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

यूपी में बंदरों के बढ़ते उत्पात पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी प्रभावी व व्यापक कार्ययोजना

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। प्रदेश में बंदरों के बढ़ते उत्पात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रभावी और व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की नेतृत्व में गठित 13 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति से कहा है कि वह केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित बैठकें कर ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करे। मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर 2026 को होगी।

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बंदरों के बढ़ते आतंक से लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, इसलिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। यह जनहित याचिका गाजियाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता विनीत शर्मा और

बीटेक छात्रा प्रज्ञा सिंघल ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि लगभग सभी जिलों में बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

प्रयागराज समेत अन्य जिलों में बंदरों के हमले की घटनाएं

कौशांबी, प्रयागराज, सीतापुर, बरेली और आगरा सहित कई जिलों में बंदरों के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। कई स्थानों पर 200-200 बंदरों के झुंड घूम रहे हैं, जिससे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, किसानों की फसलें और आम लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि शहरीकरण के कारण बंदरों का प्राकृतिक भोजन और आवास कम हो गया है, जिससे मानव-बंदर संघर्ष बढ़ा है।

अपर महाधिवक्ता ने दी जानकारी

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि आठ जनवरी की बैठक में बंदर प्रबंधन की नोडल जिम्मेदारी पर्यावरण विभाग को सौंपी गई है। रीसस मकाक (लाल मुंह वाले बंदर) की संख्या और संघर्ष वाले क्षेत्रों का फील्ड सर्वे कराया जाएगा, जिसमें लगभग एक वर्ष लग सकता है। तब तक बंदरों को पकड़ने, उनके सुरक्षित परिवहन और छोड़ने संबंधी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

याचिकाकर्ताओं की यह है मांगें

हाई कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया से जल्द अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति देने, नगर निकायों को बंदरों को पकड़ने और सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने का अभियान जारी रखने तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रस्तावित एक्शन प्लान पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पशु चिकित्सा केंद्र, रेस्क्यू वैन, बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्था और 24 घंटे शिकायत हेल्पलाइन शुरू करने की भी मांग की है।

गैंगस्टर विकास दुबे के मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी, पत्नी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। अब उनके मृत्यु प्रमाणपत्र में गड़बड़ी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर विकास की पत्नी रिचा दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

अदालत ने याचिका का संज्ञान लेते हुए स्टैंडिंग काउंसिल से जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता के पक्ष से भी हलफनामा मांगा है। इस प्रकरण में अब चार अगस्त को सुनवाई होगी। बिकरू कांड दो जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में हुआ था, जहां गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों की फायरिंग में तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र समेत आठ पुलिसकर्मी बलिदान हो गए थे।

इस घटना के बाद पुलिस ने

विकास दुबे के गुर्गों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें विकास समेत छह आरोपित मार गिराए गए थे। विकास ने नौ जुलाई की रात उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कथित तौर पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

कानपुर पुलिस जब ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर आ रही थी, तभी 10 जुलाई को सचेंडी के पास पुलिस की जीप पलट गई। मौका पाकर विकास ने फरार होने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया था। विकास के पोस्टमार्टम के दौरान पर्ची पर पिता का नाम रामकुमार के स्थान पर राजकुमार गलत दर्ज हो गया। उस समय किसी का ध्यान नहीं गया, जिससे श्मशान घाट की रसीद और मृत्यु प्रमाणपत्र में त्रुटि हुई और दस्तावेजों में विकास दुबे पुत्र राजकुमार दुबे दर्ज हो गया।

नतीजा मारे जाने के बावजूद विकास दस्तावेजों में अब तक जिंदा है। विकास की पत्नी रिचा दुबे ने इस गड़बड़ी को सही कराने की भरसक कोशिश की, लेकर यह सही नहीं हो सका। रिचा के अधिवक्ता अनुरुद्ध चतुर्वेदी ने बताया कि जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उनकी मुवक्किल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

जूते उतारकर कीचड़ में उतरे विधायक राजेश गौतम

कादीपुर, सुलतानपुर। आठ वर्षों से बदहाल दोस्तपुर-कादीपुर (सरैया बाजार) मार्ग को लेकर मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक राजेश गौतम का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। जलभराव और कीचड़ से भरी सड़क देखकर विधायक ने जूते उतार दिए और खुद कीचड़ में उतरकर हालात का जायजा लिया।

विधायक ने उपजिलाधिकारी मंजुल मयंक से कहा कि जनता वर्षों से इस सड़क के लिए परेशान है, अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को फोन पर कड़ी फटकार लगाई और जिलाधिकारी से ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई तथा संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की।

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो वह जनता के साथ सड़क पर धरने पर बैठेंगे और कार्रवाई होने तक नहीं उठेंगे।

समरथपुर–पड़रे गंदानाला सफाई पर उठे सवाल

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। तहसील बल्दीराय क्षेत्र के समरथपुर से पड़रे तक लगभग पांच किलोमीटर लंबे गंदानाले की सफाई को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सफाई कार्य केवल पुल और पुलियों के आसपास कराकर पूरे नाले की सफाई का दावा कर दिया गया, जबकि अधिकांश हिस्से में आज भी झाड़-झंखाड़ और गाद जमा है, जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है।

ग्रामीणों के अनुसार कागजों में पूरे नाले की सफाई दिखाकर लाखों रुपये का भुगतान किए जाने की आशंका है। उनका आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उनका कहना है कि यदि पूरे नाले

का निष्पक्ष स्थलीय निरीक्षण कराया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति की बात करती है लेकिन यदि उनके आरोप सही पाए जाते हैं तो यह नीति पर सवाल खड़े करता है और शासन की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। स्थानीय लोगों ने पूरे नाले का भौतिक सत्यापन, भुगतान अभिलेखों तथा माप पुस्तिका (एमबी) की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बहराइच को विकास की नई पहचान मिलेगी, विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन नहीं होगा: मुख्यमंत्री योगी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र के गौरव और भारतीय वीरों को सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने महाराजा सुहेलदेव की उपेक्षा की, जबकि विदेशी आक्रांता सालार मसूद के नाम पर गाजी मियां का मेला आयोजित कराया जाता था। डबल इंजन सरकार ने इस परंपरा को समाप्त कर स्पष्ट कर दिया है कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर स्मारक या मेला स्वीकार नहीं होगा।मुख्यमंत्री मंगलवार को बहराइच के महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों में 352 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 70 विकास

परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब महाराजा सुहेलदेव के नाम पर भव्य आयोजन और मेले आयोजित किए जाएंगे तथा सरकार इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला बहराइच आज तेजी से विकास की नई पहचान बना रहा है। उन्होंने नीति आयोग के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बहराइच ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। बुनियादी ढांचे के विकास में यह पहले, कृषि के क्षेत्र में दूसरे तथा शिक्षा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर पहुंचा है। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने जिले को 21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया है।उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को विकास कार्यों से अधिक कब्रिस्तानों की बाउंड्री और गाजी मियां का मेला आयोजित कराने की चिंता रहती थी। महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद का पराभव कर इस क्षेत्र की रक्षा की थी, लेकिन उनके गौरव को लंबे समय तक भुला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनवाकर उनके योगदान को उचित सम्मान दिया।मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए चल रही परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज तथा ऋषि बालार्क के नाम पर अस्पताल स्थापित किया गया है। लखनऊ से बहराइच तक फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 किलोमीटर लंबे बाराबंकी-बहराइच एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।उन्होंने बताया कि घाघरा (सरयू) नदी पर बाढ़ सुरक्षा के लिए 115 करोड़ रुपये की लागत से 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। रुपईडीहा-नेपाल सीमा पर औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना तैयार है। बहराइच-खलीलाबाद रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है तथा गोरखपुर से शामली तक प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर भी बहराइच से होकर गुजरेगा। इन परियोजनाओं से जिले में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच आज विकसित भारत की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। कतर्नियाघाट की प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक खेती में किसानों की भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास ने जिले की नई पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि जिले के 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक उन्नत किया गया है। इसके अलावा 32 नए राजकीय हाईस्कूल और इंटर कॉलेज, दो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा दो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। भरथापुर में दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के 500 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए नई आवासीय कॉलोनी भी विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी देश के सबसे बीमार 100 जिलों में शामिल बहराइच आज लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। पहले यहां भूमि, बालू और वन माफिया सक्रिय रहते थे तथा प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट होती थी। सत्ता के संरक्षण में अपराध और भ्रष्टाचार फलते-फूलते थे, लेकिन आज कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एजेंडे में केवल एक परिवार और एक वंश का विकास था। प्रदेश की जनता, किसान, नौजवान और महिलाओं की समस्याएं उनकी प्राथमिकता कभी नहीं रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार, अपराध और अराजकता का माहौल था, जबकि वर्तमान सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए तत्काल आर्थिक सहायता दी जा रही है।

○ संक्षेप ○

महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक, सूडा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने नगर विकास विभाग में तैनात विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है।नियुक्ति अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेश के अनुसार, महेंद्र बहादुर सिंह अपने वर्तमान पदीय दायित्वों के साथ-साथ निदेशक, सूडा के दायित्वों का भी तत्काल प्रभाव से निर्वहन करेंगे। यह व्यवस्था निदेशक, सूडा के पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त प्रभार के लिए उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ता अथवा अन्य वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।इस संबंध में विशेष सचिव विजय कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) सहित संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना के लिए भेज दी गई है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को श्रद्धांजलि, समाज ने एक अनमोल रत्न खोया : राघवेंद्र सिंह राजू

लखनऊ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज स्वर्गीय चेतन चौहान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने उन्हें समाज और राष्ट्र का एक अनमोल रत्न बताते हुए उनके व्यक्तित्व और योगदान को याद किया।राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि स्वर्गीय चेतन चौहान से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और कोरोना काल में उनके निधन से समाज ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। उन्होंने कहा कि चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट टीम के निर्भीक सलामी बल्लेबाज थे। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में अपनी प्रतिभा और संघर्षशीलता का परिचय दिया तथा सार्वजनिक जीवन में जनसेवक के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई।उन्होंने कहा कि चेतन चौहान ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि मैदान में संघर्ष कैसे किया जाता है और समाज के लिए समर्पित होकर जीवन कैसे जिया जाता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।राघवेंद्र सिंह राजू ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वर्गीय चेतन चौहान के विचारों और जनसेवा की विरासत को उनके भतीजे एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनुज चौहान आगे बढ़ाएंगे।श्रद्धांजलि सभा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों, समाज के गणमान्य लोगों एवं चौहान परिवार के सदस्यों ने स्वर्गीय चेतन चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को स्मरण किया।

मलिहाबाद पुलिस ने गैर-जमानती वारंट के आरोपी को किया गिरफ्तार

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ की मलिहाबाद थाना पुलिस ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के अनुपालन में चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है।पुलिस के अनुसार, माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंटों के अनुपालन तथा वांछित एवं वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना मलिहाबाद पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में 21 जुलाई को क्षेत्र भ्रमण, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था ड्यूटी, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग तथा वारंटियों की तलाश के दौरान पुलिस टीम ने ग्राम फिरोजपुर में दबिश देकर एक वारंटी को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान चन्द्रपाल, पुत्र स्वर्गीय महावीर पासी, निवासी ग्राम फिरोजपुर, थाना मलिहाबाद, लखनऊ के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 107/2007, केस संख्या 1029/2008 में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 447, 506 तथा वन अधिनियम की धारा 4/10 के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

नाका पुलिस ने दुकानों और वाहनों से माल चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ की नाका थाना पुलिस ने दुकानों और वाहनों में रखे माल की चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब पांच लाख रुपये मूल्य का चोरी का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।पुलिस के अनुसार, थाना नाका में अलग-अलग पीड़ितों की शिकायत पर चोरी के तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। नितीश कुमार की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 125/2026, गगन प्रसाद की शिकायत पर मुकदमा अपराध संख्या 113/2026 तथा राम सिंह की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 126/2026 पंजीकृत किया गया था। तीनों मामलों में अज्ञात चोरों द्वारा दुकानों और वाहनों में रखा माल चोरी करने का आरोप लगाया गया था।घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिम के निर्देशन में थाना नाका पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर 21 जुलाई को दुर्गापुरी झोपड़पट्टी क्षेत्र में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान (19 वर्ष) निवासी खुजरियांव, गोमतीनगर, सौरभ अरोड़ा (31 वर्ष) निवासी गीतापुरी कॉलोनी, खर्गापुर, गोमतीनगर विस्तार तथा संदीप जाटव (25 वर्ष) निवासी जिला गुना, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है।पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर खड़े वाहनों तथा उनमें रखे माल की रेकी करते थे। मौका मिलने पर अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और चोरी का सामान अपने ठिकानों पर ले जाकर छिपा देते थे।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। बरामद सामान में विभिन्न आकार की रबर की बोरियां, फायर अलार्म मशीन, एक हॉर्स पावर की दो पानी की मोटरें, 20 लीटर तेल, आरआर कंपनी के केबल तारों के आठ बंडल, फाइबर ऑप्टिक सामग्री, तांबे की चार रॉड, कोडक ट्रेसिंग पेपर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एग्जॉस्ट फैन, हार्डवेयर का सामान, आयरन सिरप, आई कैप्सूल, इंजेक्शन, वॉश बेसिन, लिक्विड के ड्रम, कूलर फैन की पत्तियां, हैंगर तथा वोल्टास कंपनी का डेढ़ टन क्षमता वाला एयर कंडीशनर सहित अन्य सामान शामिल है। बरामद सामान की कुल कीमत लगभग पांच लाख रुपये आंकी गई है।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में आवश्यक धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ग्रामीण पर्यटन से गांवों में रोजगार की नई राह, एग्री रूरल और गंगेग्राम परियोजनाओं से पर्यटन को मिल रही नई पहचान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एग्री रूरल और गंगेग्राम रूरल टूरिज्म परियोजनाओं के माध्यम से चयनित गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं के अनुरूप पर्यटन विभाग की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति, लोक कला, कृषि आधारित जीवन शैली और गंगा तटीय विरासत को पर्यटन से जोड़ते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित करना है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि परियोजना के तहत पर्यटन ग्रामों में होम-स्टे, फार्म-स्टे, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा स्थानीय महिलाओं, युवाओं, होम-स्टे संचालकों और अन्य हितधारकों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण पर्यटन को मजबूत आधार मिल रहा है और गांवों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यटन अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इससे युवा पीढ़ी पर्यटन उद्योग से जुड़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान मिल रही है। वर्ष 2024 में बागपत जिले के पूरा महादेव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2025 में बहराइच जिले के कारीकोट गांव को इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन बना ग्रामीण आत्मनिर्भरता का नया आधार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मत्स्य पालन क्षेत्र को तेजी से विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आधुनिक तकनीकों के उपयोग से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी लगातार सृजित हो रहे हैं।राज्य सरकार का उद्देश्य मत्स्य पालन को कृषि का एक लाभकारी सहायक व्यवसाय बनाकर ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन को रोकना है। इसके लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।इसी कड़ी में प्रतापगढ़ जिले के विकासखंड सण्डवा चंद्रिका के ग्राम कटका मानापुर निवासी रणंजय सिंह ने आधुनिक मत्स्य पालन अपनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है। पारंपरिक खेती से सीमित आय होने के कारण उन्होंने विभागीय प्रचार-प्रसार और समाचार माध्यमों से बायोफ्लॉक तकनीक की जानकारी प्राप्त की। जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी लगभग 0.10 हेक्टेयर निजी भूमि पर आधुनिक बायोफ्लॉक प्रणाली के तहत मत्स्य पालन इकाई स्थापित की।इस परियोजना में उन्होंने पंगेशियस प्रजाति की मछलियों का पालन शुरू किया। विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निजी बोरिंग, विद्युत संयोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गईं। कम पानी और सीमित भूमि में अधिक उत्पादन देने वाली यह पर्यावरण-अनुकूल तकनीक उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई।

सस्ते माल का झांसा देकर व्यापारी से ढाई लाख रुपये की लूट का 24 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मदेयगंज थाना पुलिस ने सस्ते दाम पर डिस्पोजल सामग्री उपलब्ध कराने का झांसा देकर व्यापारी से ढाई लाख रुपये लूटने की वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 1.92 लाख रुपये बरामद किए हैं, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।पुलिस के अनुसार, पारा थाना क्षेत्र के मायापुरम, डिप्टीखेड़ा निवासी महेंद्र कुमार एकता नगर चौराहा, ठाकुरगंज में दोना-पत्तल और डिस्पोजल सामग्री की दुकान संचालित करते हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम मोहन शेख बताया, उनकी दुकान पर आया और खुद को थोक में पन्नी एवं डिस्पोजल सामग्री का व्यापारी बताते

हुए कहा कि उसका गोदाम पक्का पुल, मदेयगंज में है। उसने बाजार से कम कीमत पर करीब 2.50 लाख रुपये का माल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।आरोपी की बातों पर विश्वास कर महेंद्र कुमार 20 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे ढाई लाख रुपये लेकर पक्का पुल पहुंचे। वहां आरोपी ने फोन पर उनसे संपर्क कर उन्हें बंधा रोड स्थित संझिया घाट के पास बुलाया, जहां उसके दो अन्य साथी पहले से मौजूद थे। जैसे ही व्यापारी ने मोटरसाइकिल की डिग्गी खोलकर रुपये निकालने का प्रयास किया, तीनों आरोपियों ने उनके हाथ से नकदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही मदेयगंज थाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 96/2026 धारा 309(2) बीएनएस के तहत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त मध्य के निर्देशन में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई।लगातार की गई कार्रवाई के दौरान 21 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस ने पक्का पुल के नीचे गोमती नदी की ओर से तीन आरोपियों मोहन शेख, सोहेल और राकिब को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1,92,000 रुपये नकद बरामद किए गए।पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी मोहन शेख ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदारों को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने का झांसा देता था।

चौथी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप-2026 का भव्य समापन

दो दिवसीय प्रतियोगिता में बाल कलाकार गार्गी की योग प्रस्तुति बनी आकर्षण का केंद्र

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ लखनऊ द्वारा परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित चौथी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप-2026 का दो दिवसीय आयोजन रविवार को क्राइस्ट चर्च कॉलेज, हजरतगंज में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्गों और स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राकेश कुमार छेत्री, सचिव, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, लखनऊ ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ नई पीढ़ी को भारत की समृद्ध

सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को भारतीय नृत्य कलाओं से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजनों का नियमित रूप से होना आवश्यक है।

डॉ. कीर्ति विक्रम सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू एवं कार्यकारी अध्यक्ष, बैटल स्पोर्ट्स डांस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने कहा कि डांस स्पोर्ट युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास करता है। ऐसे आयोजन उभरती प्रतिभाओं को अपनी कला और क्षमता प्रदर्शित करने का सशक्त मंच उपलब्ध कराते हैं तथा खेल संस्कृति को नई दिशा देते हैं।

अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती रचना गोविल, संरक्षक, बैटल स्पोर्ट्स डांस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने कहा कि जिस प्रकार ब्रेक डांस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, उसी प्रकार भारत के पारंपरिक एवं शास्त्रीय नृत्यों को भी वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए सभी संस्थाओं को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने भारतीय नृत्य शैलियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें शरीर के प्रत्येक अंग की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, जो इसे विश्व की अन्य नृत्य शैलियों से अलग पहचान प्रदान करती है। उन्होंने डांस परफॉर्मेंस को पूर्ण खेल (स्पोर्ट) के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। समापन समारोह की अध्यक्षता आनंद शेखर सिंह, चेयरमैन, बीएसएसईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने की। उन्होंने कहा कि डांस स्पोर्ट युवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं रचनात्मक विकास का सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजन नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. आनंद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एंडोक्राइन सर्जरी विभाग, केजीएमयू, लखनऊ ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से स्वस्थ, सशक्त और संस्कारित समाज का निर्माण संभव है।

प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण बाल कलाकार गार्गी द्विवेदी की मनमोहक योग प्रस्तुति रही। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उपस्थित दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। इस अवसर पर उन्हें पद्मश्री डॉ. अनिल रस्तोगी द्वारा सम्मानित भी किया गया।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि पवन सिंह चौहान, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।

विशिष्ट अतिथियों दुर्गेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकल फ्यूचर, जसपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश कराटे एसोसिएशन तथा के. बी. पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैटल स्पोर्ट्स डांस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने प्रतियोगिता की सफलता के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों, अभिभावकों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इसे और व्यापक स्तर पर आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

समारोह के दौरान विभिन्न आयु वर्गों और स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को पदक, ट्रॉफी एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और उन्हें खूब सराहना मिली। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी, विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि, प्रशिक्षक, निर्णायक, अभिभावक, खेल प्रेमी तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

राम को समझो, कृष्ण को जानो

मैंने वह समय देखा है जब चौधरी चरण सिंह ने 'असली भारत की बात करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर वह भी समय जब हिंदू भारत की हवाबाजी में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। दोनों समय का कुल परिणाम क्या? मोटामोटी राम-राम सा बोलने वाले आम हिंदुओं से धोखा। कथित असली भारत का किसान आज भी बेचारा है। वही राम के नाम पर संघ, भाजपा और नरेंद्र मोदी को जिताने वाला हिंदू अपने धर्म की ऐसी-तैसी होते देख रहा है! बिचारें 1990 की राम रथ यात्रा से 2026 में राम मंदिर के कुल 36 साला इतिहास पर? गांव-गांव से शिला-चंदा एकत्र करने से ट्रस्टियों की चढ़ावा चोरी के कथित सांस्कृतिक पुनर्जागरण वाले मौजूदा हिंदू राष्ट्रवाद पर?

इतिहास में गजनवी मंदिरों को लूटने के लिए बार-बार भारत आता था। वही हिंदुस्तान अब बतौर हिंदू राष्ट्र मंदिरों को लूटने यानी चढ़ावा खाने की आधुनिक व्यवस्थाएं लिए हुए है।

क्या मैं गलत हूं? क्या यह विचित्र हिंदू भारत नहीं है? वह भारत जिसमें संवेदना, शर्म, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व कोई नहीं है। सभी आंख-नाक-कान बंद किए ठूंठ भाव, ठूंठ हिंदू राष्ट्र बना बैठे हैं। मैंने गुरुवार को एक टीवी चैनल पर विरोधी नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता अजय राय की आलोचनाओं, विरोध के जवाब में भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहे वाक्य सुने। पहली बात, उनके चेहरे पर रत्ती भर शर्म, ग्लानि, खेद नहीं था। उन्होंने प्रभु राम की मर्यादा के हवाले कहा, हमने मर्यादा का पालन किया! ये लोग (अखिलेश, कांग्रेस) लाठी-गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखोज वे लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में राम भक्तों का अपमान हो गया। क्या तब अपमान नहीं हो रहा था?.. ये लोग नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो!

पता नहीं आदित्यनाथ ने गोरख परंपरा में योगी, पीठाधीश्वर/संरक्षक, महंत, संत के कर्तव्य, भूमिका को पढ़ा है या नहीं? इसमें लिखा है कि देवस्थान की रक्षा, दान-संपत्ति का संरक्षण, मठ की प्रतिष्ठा की रक्षा नाथ परंपरा का परम धर्म है। और ध्यान रहे, बतौर मुख्यमंत्री भी आदित्यनाथ का जिम्मा अलग है। उस नाते उनकी नाक के नीचे भक्तों द्वारा दिए गए दान और मंदिर की आय का उपयोग धर्मार्थ व संस्थागत उद्देश्यों के लिए होना था या चोरी का माल बनना था? क्यों तब वे जांच, एसआईटी की बात कर रहे हैं? जब अपने राज की परंपरा में उन्होने सीधे एनकाउंटर, बुलडोजर का रामराज्य बनाया है तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ट्रस्ट पदाधिकारियों के लिए एसआईटी क्यों, उनके सीधे एनकाउंटर का उनका बनाया राजधर्म कहां गया?

ईमानदारी से सोचें, अयोध्या में संघ के स्वयंसेवकों के ट्रस्ट की देखरेख में चढ़ावे की चोरी से भयावह राम के नाम की बदनामी दूसरी क्या है? बाबर ने तो मंदिर ढहाया था, चंपत राय एंड पार्टी ने हिंदू की उस आस्था, गर्व पर बुलडोजर चलाया है, जिसमें राम के जन्मस्थान मंदिर में, कथित हिंदू राष्ट्र के कथित रामराज्य में चढ़ावे की चोरी का एक अकल्पनीय अपराध हुआ है।

इसलिए सवाल है, गोरख संप्रदाय के एक महंत के मुख्यमंत्रीकाल में, आरएसएस के प्रचारकों के ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में चोरी की यह बदनामी किस भारत का प्रतीक है? मेरा मानना है कि कबीरदास का यह दोहा आज के हिंदू भारत के इस नए अर्थ का वाहक हैः राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अर्थात राम नाम से हिंदुओं को उल्लू बनाकर मोतियों का खजाना पाया है तो शर्म छोड़ो, संवेदनशीलता, शालीनता, मर्यादा, बुद्धि, सत्य सभी त्यागो और जितना हो सके हिंदुओं की आस्था, भरोसे को लूटो। सत्ता के इस अमूल्य अवसर को छोड़ो नहीं। क्योंकि समय खत्म होगा तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा।

तभी हिंदुओं के कलियुग का यह वह मौजूदा हिंदू भारत है, जिसे दो-ढाई हजार साल के ज्ञात भारत इतिहास में खोजें तो मालूम होगा कि हिंदुओं के साथ ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दूसरे धर्मों ने जरूर उसे लूटा, पर हिंदू हमेशा अपने धर्म के सनातन सदाचार में जीता रहा। न कभी उसकी मार्केटिंग की, न उसे बेचा, न पंडितों में मंदिर के लिए दान, चढ़ावे को संगठित रूप से लूटने की धोखाधड़ी हुई। न ही आस्था-विश्वास से धोखा कर राजनीति और सत्ता पाने का इतिहास रचा। तभी आज चढ़ावा खाने-खिलाने का दानखोर नया भारत है तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह वह सनातनी भारत भी है, जो गुजरे जमाने के इस गाने को याद कराता है, 'राम का नाम बदनाम न करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो। राम ने हंसकर सब सुख त्यागे, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाईज तुमने फ़ज़र् से आंख चुराई राम का नाम बदनाम न करो। नींद से जागो ओ मस्तानों। राम को समझो, कृष्ण को जानो।

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशनः कृषि मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि

भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मशीनीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के पूरे चक्र में विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) के माध्यम से पूरे देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आधुनिक कृषि मशीनों तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। कृषि मशीनीकरण में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उन राज्यों एवं क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां कृषि यंत्रों का उपयोग अपेक्षाकृत कम है। योजना के शुरू होने से अब तक 9,404.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के माध्यम से देशभर के किसानों को 21.61 लाख कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसके अलावा, 52.5 करोड़ रुपये की सहायता से 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र में 40,928 से अधिक ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इन प्रदर्शनों ने किसानों के बीच आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मशीनीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के पूरे चक्र में विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मशीनों, उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें भूमि की तैयारी, बुआई, सिंचाई, फसल संरक्षण, कटाई एवं कटाई के बाद के प्रबंधन जैसे सभी प्रमुख कार्य शामिल हैं। कृषि मशीनीकरण से मानव और पशु श्रम पर निर्भरता कम होती है, जिससे कृषि कार्य समय पर, अधिक दक्षता व सटीकता के साथ पूरे किए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत घटती है, श्रम उत्पादकता बढ़ती है, कृषि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आय और खेती की समग्र उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।

भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत केंद्र प्रायोजित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि मशीनों एवं उपकरणों का लाभ उन किसानों और क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इस योजना का विशेष ध्यान छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा ग्रामीण उद्यमियों पर है। यह योजना कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना को बढ़ावा देती है। ये ऐसे केंद्र हैं, जहां कृषि मशीनें, औजार और उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं। यह योजना उच्च-प्रौद्योगिकी और महंगे कृषि उपकरणों के लिए हब स्थापित करने तथा कृषि मशीनरी के वितरण में भी सहायता प्रदान करती है। इसके तहत प्रदर्शन और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाती है। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जहां कृषि मशीनीकरण का स्तर और कृषि शक्ति अपेक्षाकृत कम है। साथ ही, कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से सस्ती किराया सेवाएं उपलब्ध कराकर छोटे जोत आकार और अधिक लागत जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाता है। इसके अलावा, कृषि मशीनीकरण पर सब-मिशन के तहत कृषि मशीनरी के प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन को भी सहायता प्रदान की जाती है। इससे जुड़े हितधारकों के बीच इनका उपयोग बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। वर्ष 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की पर्याप्त स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि मशीनीकरण तथा मूल्य संवर्धन जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। वर्ष 2017-18 में इस योजना का पुनर्गठन कर इसे आरकेवीवाई-रफ्तार (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण) के रूप में लागू किया गया, जिसमें फसल-पूर्व और फसलोपरांत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया।

कृषि यांत्रिकीकरण पर सब-मिशन (एसएमएएम) को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच बेहतर बनाकर, श्रम की आवश्यकता कम करके और खेती की उत्पादकता बढ़ाकर समावेशी तथा कुशल कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। प्रशिक्षण, परीक्षण, प्रदर्शन व फसल कटाई के बाद के कामों में मशीनीकरण को बढ़ावा देनाः आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंच बढ़ाकर कृषि उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। साथ ही, कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करते हुए फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, भंडारण, मूल्य संवर्धन तथा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करता है।

खेती-बाड़ी के यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक मददः यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से कृषि मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कृषि मशीन की लागत का 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, छोटे एवं सीमांत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ड्रोन सहित मशीनीकृत कृषि सेवाओं के उपयोग के लिए प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। किराये पर मशीनें देने के लिए 'फार्म मशीनरी बैंक' (एफएमबी) बनानाः यह योजना एसएचजी, एफपीओ और स्थानीय संस्थाओं को कृषि मशीनें खरीदने के लिए 80 से 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। सीएचसी की स्थापना के लिए 250 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर कुल लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि एफएमबी की स्थापना के लिए 30 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

हाई-टेक और ज्यादा उत्पादकता वाले इक्विपमेंट हब बनानाः कार्यकुशलता बढ़ाने तथा महंगी और उन्नत कृषि मशीनों तक किसानों की पहुंच आसान बनाने के लिए फसल-विशिष्ट कार्यों हेतु उन्नत एवं उच्च क्षमता वाली कृषि मशीनरी से सुसज्जित केंद्रों की स्थापना करना सुनिश्चित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देनाः पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत लघु कृषि मशीनों पर 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 95 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

व्यंग्य

गंभीर कमियां उजागर

संक्षेप देखकर ठहर जाएं, तो मालूम होगा कि श्रम बल में भागीदारी बढ़ी है और बेरोजगारी दर घटी है। लेकिन बारीकी में जाएं, तो सकारात्मक कथानक में मौजूद कई गंभीर कमियां उजागर होने लगती हैं।

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रोजगार की स्थिति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) की ताजा रिपोर्ट चमकती हेडलाइन के लिए मसाला तो देती है, लेकिन उसके अंदर उतरते ही कड़वी हकीकतों से सामना होने लगता है। सिर्फ सार-संक्षेप देखकर ठहर जाएं, तो मालूम होगा कि श्रम बल में महिलाओं सहित कामकाजी उम्र के सभी व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ी है और बेरोजगारी दर घटी है। लेकिन बारीकी में जाएं, तो सकारात्मक कथानक में मौजूद कई गंभीर कमियां जाहिर होने लगती हैं। मसलन, यह उत्साह से बताया गया है कि बड़े शहरों में 55 फीसदी से अधिक श्रमिक अब नियमित वेतनभोगी हैं। मगर रिपोर्ट में यह तथ्य भी मौजूद है कि इनमें बहुत बड़ा हिस्सा वैसी नियमित नौकरियों का है, जिनमें पीएफ, पेंशन, सवैतनिक अवकाश, या स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षाएं नहीं मिलतीं। गिग कर्मियों की बढ़ती संख्या को रोजगार वृद्धि बताया गया है, जबकि ऐसे कर्मियों को किसी तरह के श्रम अधिकार या जॉब सिक्योरिटी हासिल नहीं हैं।

महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ कर 27.2 फीसदी होने का दावा भी विवादास्पद है, क्योंकि खुद रिपोर्ट मानती है कि कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी कम या शून्य वेतन वाले घरेलू कार्यों या असंगठित मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता है, यह स्वीकार किया गया है। बेरोजगारी दर गिर कर 4.9 प्रतिशत रह जाने की बात कही गई है, लेकिन अर्ध-रोजगार या योग्यता से कम दर्जे का काम मिलने के व्यापक चलन पर रिपोर्ट चुप है। दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत यह है कि लाखों पोस्ट-ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री धारक युवा फिलहाल महानगरों में क्लर्क, डिलीवरी बॉय या डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करने को मजबूर हैं। फिर याद रखना चाहिए कि ये रिपोर्ट मिलियन-प्लस शहरों के बारे में है। छोटे शहरों और ग्रामीण भारत की कहानी इसमें शामिल नहीं है, जहां महानगरों की तुलना में काफी कम कमाई होती है। तो एक बार फिर वही कहानी है। रोजगार के मोर्चे पर नीतिगत विफलता को छिपाने के लिए एक रिपोर्ट को इस इस तरह लिखा गया है, जिससे लोग 'फील-गुड महसूस करें।

ब्लॉग

अमेरिका ने दुनिया को अपने सपनों में गूंथा

हरिशंकर व्यास

अमेरिका ढाई सौ वर्ष का हुआ। इस शुक्रवार-शनिवार उसके जश्न की कुछ झलकियां टीवी पर देखी। एक परिचित धुन कानों में पड़ी—डोंट स्टॉप बिलीविन बरसों पुराना यह गीत मेरी पचास वर्षों की स्मृतियों को खोल गया। गीत सुन मुझे ब्रूस सप्रिंगस्टीन की आवाज़ भी याद हो आई। ब्रूस सप्रिंगस्टीन ने बॉर्न टू रन और बाद में बॉर्न इन द यू.एस.ए. को जिस अंदाज में गया, वह गजब ही था। अचानक समझ आया कि पिछले पचास वर्षों में मैंने अमेरिका को जितना समझा, पढ़ा, और उस पर जितना लिखा उससे कहीं अधिक तो उसके गीतों की जुबानी अमेरिका की यात्रा है।

संयोग है मैं पचास साल से गवाह हूं। मैं जब छोटे से कस्बे भीलवाड़ा से निकलकर दिल्ली के जेएनयू में पहुँचा था, तब मेरे भीतर भी एक दौड़ शुरू हुई थी। दुनिया को जानने की, समझने की, पढ़ने की और अपनी टूटी-फूटी हिंदी में उसे लिखने की। वह आपातकाल का समय था। मेरे लिए जेएनयू की लाइब्रेरी कौतुकता के मेरे डीएनए की मानों पूर्ति थी। विदेशी पत्र-पत्रिकाएं, अखबार, विश्लेषण—जो हाथ लगा, पढ़ता था। उसी से संयोग बना और कुछ ही महिनों में मैंने वैश्विक घटनाओं पर लिखना शुरू किया। 16 दिसंबर 1976 को दैनिक हिंदुस्तान में पहला लेख छपा, वह भी अंतरराष्ट्रीय विषय पर। तब भारत में आपातकाल था। इसलिए हिंदी अखबारों को दुनिया पर लिखा चाहिए था और सुरक्षित भी था। इसलिए सोवियत संघ, अमेरिका, यूरोप और शीतयुद्ध की राजनीति मेरा शगल बनी। कुछ ही महीनों में दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं से लेकर राजेंद्र माथुर के नेतृत्व वाले नई दुनिया में परिक्रमा कॉलम लिखने का मेरा सिलसिला बना, पत्रकारिता की भूमिका बनी। उन दिनों चालीस, साठ और पचहत्तर रुपए प्रति लेख मिलते थे। आवश्यकता से अधिक। नतीजतन कनॉट प्लेस की सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी से टाइम, द इकोनॉमिस्ट, हिम्मत, ओपिनियन, क्वेस्ट जैसी पत्रिकाएं खरीदता। बगल के प्रिया और चाणक्य सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्में देखता। दुनिया को पढ़ने के साथ-साथ देखने की आदत भी बनी। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेज़नेव का समय था। अब ट्रंप और पुतिन का है। 1975-76 का अमेरिका आज भी मेरी स्मृति में बहुत साफ़ है। सैगॉन में अमेरिकी दूतावास की छत से हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने की तब तस्वीरें थीं। राष्ट्रपति निक्सन और वाटरगेट कांड की गूंज थी। 1976 में अमेरिका के दो सौ वर्ष पूरे हुए। उत्सव हुआ, मगर अमेरिका में युद्ध हारने की पीड़ा थी, गहरी निराशा थी। सत्ता पर अविश्वास था और भविष्य को लेकर अनिश्चितता।

उसी दौरान ब्रूस सप्रिंगस्टीन का संभवतः पहला बड़ा गीत बॉर्न टू रन सुपरहिट हुआ। वह तब एक पीढ़ी की बेचैनी की आवाज़ था, जो कह रही थी—यहां दम घुट रहा है, कहीं निकल चलो। छोटे शहर से बाहर निकलो। सीमाएं तोड़ो। अपना भविष्य खुद बनाओ। सप्रिंगस्टीन अमेरिकी मजदूर, छोटे शहरों और अमेरिकी सपने की प्रामाणिक आवाज़ बन गए। वह आवाज़, जो रोनाल्ड रीगन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को ठेंगा दिखाती रही है। क्योंकि उनकी आवाज़ में अमेरिकी सत्ता नहीं, बल्कि व्यक्ति और नागरिक के सपनों का अमेरिका है। वह अमेरिका, जहां व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रतिभा से अपना भविष्य गढ़ता है। खुद अवसर खोजता है, मेहनत से अपने सपनों को साकार बनाता है। फिर 1981 में एक गीत आया -डोंट स्टॉप बिलीविन। जर्नी बैंड के गायक स्टीव पेरी की आवाज़ के इस गीत ने 1981 अमेरिका को ऐसा बांधा कि आज भी वह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसकी शुरुआती पंक्तियां—एक छोटे कस्बे की लड़कीज और एक छोटे कस्बे का लड़काज—सीधे अमेरिकी मानस को छू गई। साधारण परिवार, छोटे शहर पर बड़े सपने।

गीत का संदेश जो टूक यह कि —उम्मीद मत छोड़ो। विश्वास बनाए रखो। मतलब अमेरिका सपनों के लिए, विश्वास के साथ है।

तब से अब तक आर्थिक मंदी हो, व्यक्तिगत संकट हो, खेल का मैदान हो या राष्ट्रीय उत्सव—अमेरिका में गीत हर जगह गाया जाता है। ढाई सौवें स्थापना दिवस के समारोह में जब हजारों अमेरिकी इसके अंतिम कोरस तक एक साथ पहुंचे, तो सचमुच लगा कि वे गीत नहीं मात्र नहीं गा रहे थे वे निज विश्वास में देश को अभिव्यक्त कर रहे हैं।

अचानक मन में प्रश्न उठा। क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसे गीत है, जिसे पूरा समाज अपने साझा सपने की तरह गाता हो? रूस, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान या भारत—हर देश के पास अपने राष्ट्रगान है, देशभक्ति के गीत हैं, युद्ध के गीत हैं, क्रांति के गीत हैं। लेकिन क्या ऐसे गीत है, जो साधारण नागरिक से इतना भर कहे—सपने देखो, हार मत मानो, आगे बढ़ो, विश्वास रखों?

यही अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अधिकांश देशों ने अपने नागरिकों को इतिहास, धर्म, राजसत्ता, जातीय गौरव या राष्ट्रीय अस्मिता के आधार पर जोड़ा या बनाया। मगर अमेरिका ने वेयक्तिक, निज सपनों से देश गढ़ा। अमेरिका में जो रहा है, जो हुआ या होगा, उसमें निज मनुष्य के सपनों की पहली भूमिका है फिर संविधान, प्रशासन, राष्ट्रपति की है। डोनाल्ड ट्रंप हों या इलॉन मस्क, कमला हैरिस हों या सुंदर पिचाई—सबकी कहानियों का आरंभ एक ही जगह से होता है—वह स्वतंत्र मनुष्य के सपने से है। इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका को समझना हो तो उसके राष्ट्रपतियों से पहले उसके गीतों को सुने। साफ जाहिर होगा कि वे अमेरिका कैसे सोचता है, कैसे टूटता है, कैसे संभलता है और क्यों हर संकट के बाद भी अपने भविष्य पर विश्वास बनाए रखता है।

अमेरिका का राष्ट्रगान द स्टार स्पैंगल्ड बैनर है। इसे 1814 में फ्रांसिस स्कॉट की ने बाल्टीमोर के युद्ध के दौरान लिखा था। इसकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है—ओअर द लैंड ऑफ द फ्री एंड द होम ऑफ द ब्रेव—यानी स्वतंत्र लोगों की भूमि और वीरों का घर। यह गीत युद्ध के बीच झंडे के बच जाने का गीत है। गणराज्य की रक्षा का गीत है। लेकिन अमेरिका और अमेरिकियों का सपना राष्ट्रगान में नहीं बसता। वह लोकप्रिय गीतों में सांस लेता है। यदि राष्ट्रगान बताता है कि अमेरिका कैसे बचा, तो उसके गीत बताते हैं कि अमेरिका किस विश्वास पर खड़ा हुआ था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसलिए अमेरिका भूगोल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। वह अपने नागरिकों से पहले यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, किस धर्म, किस जाति या किस वंश से आए हो। वह उनके सपने देखता है, सपनों को मौका देता है। इसलिए दुनिया भर के लोग ढाई सौ वर्षों से अपने सपने लेकर मुख्यतः अमेरिका की ओर ही भागे हैं। बिरले ही मनुष्य होंगे जो सपने लेकर चीन, रूस, भारत या किसी और देश में जाएं।

लोगों के लिए अमेरिका कमाई से पहले सपनों को साकार बनाने का मुकाम है। दुनिया के बाकी देश अपने को मदरलैंड, फादरलैंड या धर्मराष्ट्र कहते हैं, मगर अमेरिका अकेला ऐसा देश है, जहां सपना पहले है, बाकी सब बाद में। पहले सपना, फिर पूंजीवाद। कोलंबस जब समुद्र में निकला था, तब उसके पास कोई निश्चित नक्शा नहीं था। उसके पास केवल विश्वास था कि क्षितिज के पार कुछ नया मिलेगा। उसी खोज की मानसिकता ने बाद में पूरे अमेरिकी महाद्वीप का चरित्र गढ़ा। अमेरिका का जन्म किसी नस्ल विशेष, भाषा या धर्म से नहीं हुआ। उसका जन्म एक संभावना से हुआ जिसका संबल विश्वास था।

तभी अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात हथियार से ज्यादा पूरी पृथ्वी को सपनों की और दौड़ाने वाला देश है। अमेरिकी संविधान का मूल भाव है कि यदि तुममें प्रतिभा है, जोखिम उठाने का साहस है और मेहनत करने की इच्छा है, तो भविष्य तुम्हारा हो सकता है। यही उसका मूल सूत्र और सांस्कृतिक ताकत है।

अमेरिका में राष्ट्रपति, सरकारें बदलती रहती हैं। नीतियां बदलती रहती हैं। कभी उदारवाद, कभी अनुदारवाद, कभी राष्ट्रवाद। कभी निक्सन और रीगन हैं, तो कभी ओबामा, कभी ट्रंप। लेकिन इन सबके बीच एक चीज़ लगातार है और वह यह विश्वास है कि हम कर सकते हैं, फिर महान बन सकते हैं, दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं और एक दिन चंद्रमा या मंगल पर भी बस सकते हैं।

वेयक्तिक सपने से कोई कब अमेरिका पहुंचता है और कैसे वही एक सपना अमेरिकी स्वप्न का रॉकेट बनता है और फिर वह दुनिया से लेकर अंतरिक्ष के मिशन में खरबपति और ब्रह्मांड का खोजी बन बैठता है—इसकी कहानी केवल इलॉन मस्क की नहीं है। यह अमेरिकी सभ्यता की तासीर है। तभी वहा का संगीतकार और गायक भी दुनिया को थिरकाता हैं तो अमेरिका में विश्वास का जज़्बा भी बनाए रखता हैं। अमेरिका की सांस्कृतिकता हो, उसका उपभोक्तावाद हो या उसका पूंजीवाद—सब व्यक्ति के सपनों से है। अब सपनों की यह फितरत तो होती ही कि वे सर्वभूमि गोपाल की तरह हर दिशा में फुदकते हैं।

तभी अमेरिका ने दुनिया को अपने सपनों में गूंथा है। मैंने पहली बार पेरिस के डिज़्नीलैंड में इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड गीत सुना, तब गहराई से अहसास हुआ कि अमेरिका केवल सामान या हथियार नहीं बेचता, वह कल्पनाएं भी बेचता है। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड मनभावत, नौका यात्रा बताती है कि दुनिया छोटी है। लोग अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन बच्चों की मुस्कान, भविष्य की आशा और मनुष्य के सपने हर जगह एक जैसे हैं। यह गीत शीतयुद्ध के दौर में बच्चों के लिए बना था, मगर तब भी वह अमेरिकी सॉफ्ट पावर का सांस्कृतिक घोषणापत्र था—दुनिया को जोड़ो, बांटो मत। डिज़्नी का ही एक और मनभावन गीत है—देयर्स अ ग्रेट बिग ब्यूटीफुल टुमारो। भविष्य के प्रति अटूट विश्वास का यह संगीत और संदेश कहता है कि हर दिन के अंत में एक और बेहतर कल हमारा इंतजार कर रहा है। यही मनोविज्ञान विज्ञान, तकनीक, उद्योग और खोजों के पीछे है। भविष्य अतीत से बड़ा होगा। और अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर जीवन जिएगी।

अमेरिकी सपनों ने केवल हॉलीवुड नहीं बनाया। उसने दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और तकनीक भी दी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई भी सपने, विश्वास की उपज हैं। अमेरिका ने डॉलर को वैश्विक करेसी बनाया तो दुनिया को सपने देखने की भाषा भी दी। उसकी फिल्में, उसका संगीत, उसके विश्वविद्यालय, उसकी तकनीक, उसके बाजार—सब मिलकर एक ही संदेश देते है सपने देखो, भागों, दौडों, कंपीट करों और भविष्य बनाओ।

अमेरिका की वास्तविक शक्ति व्हाइट हाउस नहीं है। वह उन करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बसने वाली उस धुन और विश्वास में है, जो लोगों को सुबह यह मानकर उठाती हैं कि आज का दिन कल से बेहतर हो सकता है। तभी एक मायने में पिछले पचास वर्षों का अमेरिकी संगीत अमेरिका की जीवनी है। बॉर्न टू रन कहता है—सीमाएं तोड़ो और आगे बढ़ो। डोंट स्टॉप बिलीविन कहता है—विश्वास मत खोओ। देयर्स अ ग्रेट बिग ब्यूटीफुल टुमारो कहता है—भविष्य पर भरोसा रखो। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड कहता है—दुनिया एक साझा मानव परिवार है। इन्ही सबसे अमेरिकी समाज की आत्मा है।

गाजियाबाद के हैवान बेटे! मां-बाप को पीट-पीटकर मार डाला, दोनों अरेस्ट...

मकान में रहने वाले किरायेदार ने बुलाई पुलिस

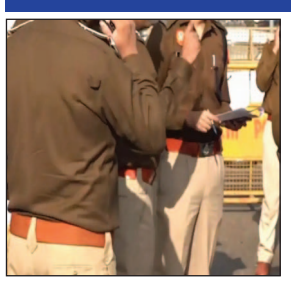

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। वीर नगर मोहल्ले में दो बेटों ने अपने ही माता-पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, घटना देर रात की है। डायल-112 पर एक किरायेदार ने सूचना दी कि उसके मकान मालिक गंगाशरण, उनकी पत्नी विमलेश और उनके दोनों बेटे दीपक व ललित के बीच घर के अंदर झगड़ा हो रहा है। सूचना में यह भी बताया गया कि विवाद के दौरान गंगाशरण और विमलेश को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर में घायल अवस्था में मिले दंपती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने मृतक दंपती के दोनों बेटों दीपक और ललित को गिरफ्तार कर लिया गया है।दोनों से अलग-अलग और संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विवाद किस वजह से हुआ और घटना किन परिस्थितियों में अंजाम दी गई।

पुलिस शुरुआती जांच में इसे पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला मान रही है। हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

किरायेदार की सूचना से खुला मामला

इस पूरी घटना का खुलासा उस समय हुआ जब मकान में रहने वाले एक किरायेदार ने झगड़े और मारपीट की आवाज सुनकर डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। अगर समय रहते सूचना नहीं दी जाती, तो घटना का पता लगने में और देर हो सकती थी। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए जा सकें।

पुलिस ने क्या कहा?

ग्रामीण पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के वीर नगर मोहल्ले से डायल-112 पर झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंगाशरण और उनकी पत्नी विमलेश को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मामले में दोनों बेटों दीपक और ललित से पूछताछ की जा रही है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर हत्या की वजह और घटना का पूरा घटनाक्रम स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा से सशक्तिकरण की ओर बढ़ा स्पेक्ट्रम ग्रुप

आर्यावर्त संवाददाता

कूरेभार/सुल्तानपुर। अद्वैत फाउंडेशन द्वारा संचालित स्पेक्ट्रम ग्रुप के तत्वावधान में छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कूरेभार थानाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह तथा वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ उपस्थित रहे। थानाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार के 'मिशन शक्ति' अभियान की जानकारी देते हुए छात्राओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों तथा विषम परिस्थितियों में पुलिस की सहायता प्राप्त करने के तरीकों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस प्रशासन हर समय आमजन की सहायता के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में पुलिस टीम ने साइबर सुरक्षा पर विशेष सत्र आयोजित कर विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने तथा सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही 112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (वुमेन पावर लाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 102/108 (एम्बुलेंस सेवा) एवं 1930 (साइबर हेल्पलाइन) के महत्व और उपयोग की विस्तृत जानकारी भी दी। संस्थान की ओर से प्रबंधक आनंद सावरण, एचआर मैनेजर अनूप मिश्र, ऑपरेशनल मैनेजर ज्योति शर्मा, विवेक वर्मा, अभिषेक पाण्डेय, विनय सिंह, दीप्ती साहू, सुशील चौधरी, विख्यात दत्त मिश्र, रूचि पाण्डेय एवं मंजू लता सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला व तहसील के अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य से आज विरत रहने की अपील

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उ०प्र० प्रयागराज द्वारा किये जा रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन में न्यायिक कार्य से विरत रह कर 22 जुलाई को समर्थन की अपील की गई है। संयुक्त सचिव प्रेस सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि अध्यक्ष राजस्व परिषद उ०प्र० लखनऊ द्वारा 03 जुलाई 2026को तीन सदस्यीय पीठ एवं 08 जुलाई 2026 पांच सदस्यीय पीठ एवं रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के विरूद्ध जाकर लखनऊ से वाद सूची के प्रकाशन व प्रयागराज स्थित पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोई भी तिथि निर्धारित न कर सकने के विरोध में आम सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार कल 22 जुलाई को राजस्व परिषद प्रांगण में विरोध दिवस मनाया जायेगा। बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उ०प्र० प्रयागराज के लाईब्रेरी हाल में हुई आम सभा में लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के समस्त हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कमिश्नरी बार, जनपद न्यायालय बार, तहसील बार से सहयोग की अपील की है। संयुक्त सचिव प्रेस सुरेन्द्र कुमार ने प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अपील की कि बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उ०प्र० प्रयागराज के आवाहन पर कल 22 जुलाई को अपने अपने मण्डल व जनपद एवं तहसील स्तर पर न्यायिक कार्य से विरत रह कर अपना पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें। आम सभा में अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सिंह, रमेश पुण्डीर, कल्लन उर्फ विजय शंकर तिवारी, अरूणेश खरे, राजेश प्रताप सिंह, सुनिल वर्मा, महासचिव अनिरूद्ध शर्मा, रोहित शर्मा, सूर्य कान्त शर्मा, मनीष कुमार पाण्डेय, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रशान्त उपाध्याय समेत सैकड़ो अधिवक्ता उपस्थित रहे।

अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर लेबर रूम में पैदल जा रही थी गर्भवती महिला, हो गई डिलीवरी, फर्श पर गिरने से नवजात की मौत का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

बहराइच। यूपी के बहराइच जिले में स्थित महिला अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामले सामने आया है, जिसे चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। परिजनों का आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके चलते उसे पैदल ही लेबर रूम ले जाया जा रहा था। इसी दौरान महिला का प्रसव हो गया और नवजात फर्श पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला जिले के मामला हरदी थाना क्षेत्र का है।

थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ग्राम पंचायत के नेपालपुरवा गांव की रहने वाली गर्भवती ज्योति को प्रसव पीड़ा होने पर उनके पति अमित शुक्ल ने रविवार को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के मुताबिक, डॉक्टर ने जांच के बाद अल्ट्रासाउंड कराया और सोमवार सुबह दवा दी गई। दोपहर करीब 3 बजे प्रसव पीड़ा तेज होने पर उन्होंने स्ट्रेचर की मांग की, आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध कराया। आरोप है कि मजबूरी में परिजन गर्भवती को पैदल ही लेबर रूम ले जा रहे थे। रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई और नवजात फर्श पर गिर गया। परिजनों का कहना है कि इसी वजह से बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

जांच के लिए समिति गठित

मामले की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ। संजय खत्री, प्रोफेसर डॉ। अमित श्रीवास्तव और सीएमएस डॉ। एस।के। वर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों के बयान दर्ज किए और पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी।

किसकी लापरवाही?

वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार महिला के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। प्राचार्य डॉ। संजय खत्री ने कहा कि महिला वार्ड से बाहर पैदल कैसे निकली, इसकी जांच कराई जा रही है। शुरुआती जांच में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर और तीन स्टाफ नर्सों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

जौहर विवि के ध्वस्तीकरण के खिलाफ एआईएमआईएम का प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। मोहम्मद अली जौहर विश्विद्यालय जनपद रामपुर और पूरे भारत की एक पहचान है। यहां के गरीब मध्यम वर्ग वा आने वाली नस्लों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। हज़ारों छात्र छात्राएं यहां से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसका ध्वस्तीकरण न होने दिया जाय। इसी को लेकर आज ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम महानगर अध्यक्ष अफ़सर महमूद व अली शेर खान जिलाध्यक्ष गंगापार की पूरी टीम जिला मुख्यालय पर पहुंच कर ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए अपार जिला अधिकारी सत्यम मिश्रा के द्वारा राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर विश्विद्यालय को जिस तरह से ध्वस्त करने का आदेश पारित हुआ है। यदि ऐसा होता है तो रामपुर सहित पूरे देश की शिक्षा के क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा और यहां के नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हम सभी का यह मानना है कि यह किसी पार्टी या व्यक्ति का मामला नहीं है यह शिक्षा और यहां के नौजवानों के भविष्य का मामला है। शिक्षा के इस मंदिर को बचाना सरकार और हम सब की जिम्मेदारी है। इस क़दम से प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होगी। एआईएमआईएम सरकार से यह मांग करती है कि वह मोहम्मद अली जौहर विश्विद्यालय ध्वस्त करने की कार्यवाही को तुरंत रोका जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से शारिक कलीम युवा जिलाध्यक्ष गंगापार, महानगर प्रवक्ता इफ्तेखार अहमद मंदर, रियाज़ुल हक़ चौधरी,इमरान अहमद बख़्शी, माबूद आलम,मोहम्मद अली, मोहम्मद कौशैन, मोहम्मद अफजल, तरन्नुम, नाजनीन, रुखसाना, इमराना, मोहम्मद अयाज़, आदि लोग उपस्थित थे।

रामपुर में दो पत्नियों के बीच फंसा पति... पंचायत ने सुनाया अनोखा फैसला, युवक पर लागू किया गजब फार्मूला

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर। यूपी के रामपुर जिले में एक पंचायत ने अनोख फैसला दिया, जिसकी चर्चा जिले भर में हो रही है। पंचायत का फैसला दो शादियों के बाद एक परिवार में चल रहे विवाद को लेकर दिया गया है। पहली पत्नी की शिकायत और पारिवारिक विवाद के बाद हुई पंचायत में फैसला लिया गया कि पति सप्ताह में तीन दिन पहली पत्नी और तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, जबकि सातवें दिन वह अपनी मर्जी से समय बिताएगा। साथ ही पहली पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी पंचायत में तय की गई। मामला जिले के दढ़ियाल पुलिस चौकी क्षेत्र का है।युवक की पहली शादी करीब 14 साल पहले हुई थी और उससे दो बेटियां हैं। बाद में उसने पहली पत्नी की सहमति के बिना दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी दो बेटियां होने के बावजूद वह अधिकतर समय दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा, जिससे पहली पत्नी ने उपेक्षा और खर्च न मिलने की शिकायत पुलिस से की थी। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के परिजन और गांव के लोगों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई। लंबी चर्चा के बाद लिखित समझौता हुआ कि पति सोमवार से बुधवार तक पहली पत्नी के साथ रहेगा, गुरुवार से शनिवार तक दूसरी पत्नी के साथ, जबकि रविवार को वह अपनी इच्छा के अनुसार रहेगा। इसके अलावा पहली पत्नी के लिए हर महीने राशन उपलब्ध कराने और साप्ताहिक खर्च देने पर भी सहमति बनी।

दोनों पक्षों ने माना पंचायत का फैसला

दोनों पक्षों ने पंचायत के फैसले को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पहली पत्नी ने अपनी शिकायत आगे नहीं बढ़ाई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की सहमति से समझौता होने के बाद मामले का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर दिया गया है। इस पंचायत और फैसले की चर्चा जिले भर में हो रही है।

आंधी तूफान एवं वज्रपात से बचाव को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

प्रयागराज। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी के अनुसार जनपद प्रयागराज एवं आसपास के क्षेत्रों में अलग 20 जुलाई से 23 जुलाई तक आंधी/तुफान, आकाशीय विद्युत, बारिश एवं तेज हवा की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। जिसके दृष्टिगत जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि थदि आंधी आने लगे तो टिन की छत, होर्डिंग, क्षतिग्रस्त मकान, पेड़, बिजली के खंभे एवं मोबाइल टावर से दूर रहें। घर के बाहर या छत पर रखी हुई भारी वस्तुएं उड़ सकती हैं, इसलिये उन्हें बांधकर रख दें। साथ ही यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाएं। यह भी कहा गया है कि धारदार एवं नुकीली वस्तुओं को खुले में ना रखें। धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें एवं पेड़ की शरण में ना जायें ।

चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर में मास फायरिंग! गणना में जुटे कर्मियों की छुट्टी, अब नए लोगों की एंट्री

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जहां एक तरफ SIT की जांच जारी है तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर में नई व्यवस्था लागू की गई है। इस बीच खबर है कि दान पात्रों में जमा होने वाले नकद चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब नए लोगों को रखा गया है।

जानकारी के मुताबिक मंदिर में कर्मियों की मास फायरिंग हुई है। चढ़ावा चोरी कांड के बाद लगातार कई बदलाव किए जा रहे हैं और चढ़ावे की गिनती में अब नई टीम की एंट्री हुई है। इसे व्यवस्था में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। पहले की टीम से अचानक 23 लोगों ने काम छोड़ दिया था जिसके बाद पुरानी टीम से केवल 13 लोग ही बचे थे। वहीं अब खबर आ रही है कि इन 13 लोगों

को भी हटा दिया गया है। पुराने किसी भी कर्मी को गिनती करने वाली टीम में जगह नहीं दी गई है।

आई कार्ड और ड्रेस ली वापस

बताया जा रहा है कि इन कर्मियों के आई कार्ड और ड्रेस भी जमा करवा लिए गए हैं।यानी इन लोगों को अब मंदिर परिसर में किसी और काम पर भी नहीं लगाया जाएगा। इन लोगों को अब कल से काम पर ना आने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कर्मी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट के रिकमेंडेशन पर SBI द्वारा काम पर रखे गए कर्मी थे।

SBI की निगरानी में गिनती

जानकारी के मुताबिक फिलहाल SBI के स्टाफ ही गिनती के काम में लगे हैं। अलग-अलग ब्रांच से भी SBI ने अपने परमानेंट स्टाफ को राम मंदिर में चढ़ावा गणना के काम पर लगाया है। चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी SBI की निगरानी में संचालित की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित रहे।

निकाले गए कर्मियों ने क्या कहा

हाउसकीपिंग स्टाफ को कद चढ़ावे की गिनती में लगाने पर SBI की लापरवाही पर भी सवाल उठे थे। ऐसे में बैंक की तरफ से अब ज्यादा तत्परता दिखाई जा रही है। वहीं जिन कर्मियों को अचानक काम से हटाया गया उनकी शिकायत है कि एक कर्मी के नाम पर बैंक ट्रस्ट से 26000 रुपए लेता था वहीं उन्हें 15000 रुपए ही दिए जाते थे। उनका कहना है कि अब वो भी उनसे अचानक छीन लिए गए जबकि उनकी इन मामले में कोई गलती नहीं थी।

भाजपा में भी लागू हो सकता है सपा-रालोद गठबंधन वाला फार्मूला,सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में बातचीत

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ।मिशन- 2027 को फतह करने के लिए भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का तालमेल बनाने में जुट गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के बीच सीट बंटवारे पर सपा वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है।

इसमें सिंबल रालोद का और चेहरा भाजपा का होगा। दोनों दलों के नेता एक-दूसरे दलों में अपने संबंध मजबूत करने में लगे हैं। सीट बंटवारे को फाइनल करने के लिए दोनों दलों के बीच लंबी सियासी खींचतान भी चलेगी।

प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। पश्चिम के सियासी गलियारों में भाजपा-रालोद गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान भी होनी शुरू हो गई है। भाजपा-रालोद के बीच सीट बंटवाने में चौंकाने वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है।

यह फॉर्मूला कोई नया नहीं, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमाया गया सपा-रालोद गठबंधन वाला मॉडल है। इस नए समीकरण के तहत पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर "सिम्बल रालोद का और नेता भाजपा का"दांव खेला जा सकता है।

यह है "सपा-रालोद"वाला पुराना फॉर्मूला

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब सपा- रालोद में गठबंधन था, तब कई सीटों पर सपा के कद्दावर नेताओं ने रालोद में शामिल होकर उसके सिंबल पर चुनाव लड़ा था। इनमें मेरठ की सिवालखास सीट से उस समय सपा नेता रहे गुलाम मोहम्मद रालोद में शामिल होकर हैंडपंप सिंबल पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे।

इसी तरह से सपा के राजपाल सैनी ने भी रालोद सिंबल पर खतौली से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उनको हार का सामना करना पड़ा। बाद में खतौली में हुए उप चुनाव में रालोद के मदन भैया चुनाव जीते थे। मीरापुर विधानसभा सीट पर भी सपा नेता चंदन चौहान ने रालोद में शामिल होकर उसके सिंबल पर चुनाव जीता था।

सपा नेता रहे अनिल कुमार ने भी पुरकाजी सीट पर रालोद में शामिल होकर चुनाव जीता। इसी तरह से चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद मीरापुर सीट पर उप चुनाव हुआ तो भाजपा नेत्री मिथिलेश पाल ने रालोद में शामिल होकर उसके सिंबल पर चुनाव लड़ा और विधायक बनी।

इस समीकरण का मुख्य कारण

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं, जो पारंपरिक रूप से जाट बाहुल्य हैं, लेकिन वहां भाजपा के पास मजबूत और जिताऊ चेहरे हैं। ऐसे में गठबंधन धर्म को निभाते हुए और सीट रालोद के खाते में जाने की स्थिति में भाजपा के नेता रालोद के सिम्बल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।

नेताओं ने शुरू कर दिया इधर-उधर होने का खेल

इस फॉर्मूले की भनक लगते ही दोनों दलों के नेताओं में अभी से बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा और रालोद दोनों ही दलों के टिकटार्थी और वर्तमान विधायक एक-दूसरे के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय संगठन के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुट गए हैं।

कुछ ऐसे नेता जो वर्तमान में भाजपा में हैं लेकिन संभावित सीट बंटवारे में अपनी सीट रालोद के खाते में जाने की संभावना देख रहे हैं, वे जयंत चौधरी के दरबार में हाजिरी लगाने लगे हैं। वहीं रालोद के कुछ नेता भी भगवा खेमे के संपर्क में हैं।

इस फॉर्मूले की सियासी वजह

रालोद ने जिन 33-35 सीटों पर दावा ठोका है, उनमें से कई पर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। विधायकों का टिकट कटने से रोकने के लिए यह सिम्बल ट्रांसफर सबसे मुफीद रास्ता है। रालोद के सिम्बल पर भाजपा का चेहरा होने से जाट-मुस्लिम-मजदूर समीकरण के साथ-साथ भाजपा का पारंपरिक गैर-जाट ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक भी आसानी से ट्रांसफर होने की उम्मीद है।

दिल्ली जंतर मंतर लाठीचार्ज पर वकीलों का प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध में सोमवार को जिला कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कचहरी के बाहर सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। इस कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ और आसपास भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर विचार करने के बजाय उन पर बल प्रयोग करना स्वाभाविक रूप से विरोध को जन्म देगा। उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर जवाब देने की मांग की। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद वकीलों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सड़क से जले टायर हटवाकर यातायात सामान्य कराया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद जिला कचहरी के आसपास सामान्य स्थिति बहाल हो गई और यातायात सुचारु रूप से चलने लगा।

घर पर ही बस 2 चीजों से बनाएं विंटर नाइट सीरम, सुबह खिला-खिला मिलेगा चेहरा

सर्दियों में त्वचा का रूखा और बेजान होना आम बात है। हालांकि, इसे सॉफ्ट बनाना भी आसान है। इसके लिए आप घर पर ही 2 चीजों से एक नाइट सीरम बना सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं सीरम बनाने का आसान तरीका और इसके फायदे।

सर्दियों ने दस्तक दे दी है। नवंबर का महीना शुरु हो गया है...वातावरण ठंडा होने लगा है। बदलते मौसम के साथ ही त्वचा का रूखापन और ड्राई होना भी शुरु हो गया है। सर्दियों के मौसम में लोग अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखने के लिए कोल्ड क्रीम और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें ऑयल ज्यादा होने की वजह से स्किन सॉफ्ट तो बनती है लेकिन बेजान से हो जाती है। चेहरे का खिलापन कम होने लगता है। इसलिए आपको जरूरत है एक ऐसे सीरम की जो चेहरे को नमी के साथ ही खिला हुआ बनाएं।

आज इस आर्टिकल में हम आपको बस 2 चीजों से बनने वाला सीरम बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप नाइट स्किन केयर रूटीन में करें और सुबह पाएं खिली-खिली और ग्लोइंग स्किन। इसका इस्तेमाल महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं होममेड सीरम बनाने का पूरा तरीका।

नेचुरल चीजों से बनाएं विंटर सीरम

सर्दियों में आप अपनी बुझी हुई स्किन को चमकाने और खिला हुआ बनाने के लिए घर पर ही 2 चीजों से विंटर नाइट सीरम बना सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल और गुलाब जल। एलोवेरा स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें ऐसे गुण और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो त्वचा की तमाम समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। जैसे एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और बी12 पाया जाता है। वहीं, गुलाब जल भी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बी, सी और ई, और फ्लेवोनोइड्स का अच्छा सोर्स है।

कैसे बनाएं विंटर नाइट सीरम

विंटर नाइट सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा का जेल निकाल लें। अब इसमें गुलाब जल मिलाकर इसे मिक्स करें। एलोवेरा में इतना गुलाब जल मिलाएं जिससे वो पतला हो जाए, ताकि स्प्रे करने में आसानी हो। अब इसे मिक्स करके एक स्प्रे बोतल में भर लें। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला सकते हैं। ये स्किन को एक अलग चमक देगा। आप इस स्प्रे को कम से कम 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं।

विंटर नाइट सीरम इस्तेमाल करने का तरीका

2 चीजों से बने इस सीरम को आपको नाइट स्किन केयर रूटीन में अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को धो लें और साफ कपड़े से पोंछ लें। अब सीरम को चेहरे पर स्प्रे करें या किसी कॉटन पैड की मदद से अप्लाई करें। ध्यान रहे कि सीरम अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है। सीरम जब स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए तभी स्किनकेयर का अलग स्टेप फॉलो करें। इस सीरम को लगातार 21 दिन लगाने के बाद आपको अपने चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो देखने को मिलेगा। साथ ही स्किन बनेगी सॉफ्ट और बेदाग।

सेब से बनाई जा सकती हैं 5 तरह की लजीज चटनी, इनकी रेसिपी भी है आसान

सेब से केवल जूस ही नहीं, बल्कि कई तरह की चटनी भी बनाई जा सकती हैं। ये न केवल भोजन को एक नया स्वाद देती हैं, बल्कि इस फल के पोषण भी प्रदान करती हैं। आज के लेख में हम आपको 5 तरह की सेब की चटनी की रेसिपी बताएंगे। इन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और रोजमर्रा के खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। इनको आप रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं।

सेब की मीठी चटनी

सेब की मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और उसे पैन में डालें। इसमें थोड़ी चीनी, नींबू का रस, अदरक का रस और दालचीनी पाउडर डालें। इसे मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक की सेब नरम न हो जाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके पीस लें और फिर इसे किसी बंद डिब्बे में भरकर रखें। यह चटनी कई दिनों तक फ्रिज में रखी जा सकती है।

सेब की तीखी चटनी

सेब की तीखी चटनी बनाने के लिए सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इस मिश्रण में नमक, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक और पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। यह चटनी खान-पान में तीखा स्वाद जोड़ देगी।

सेब की करी पत्ते वाली चटनी

सेब की करी पत्ते वाली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और छील लें। उसे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और करी पत्ता के साथ पकाएं। अब इस मिश्रण में नमक, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सब्जियां नरम हो जाएं और अच्छी खुशबु आने लगे। यह चटनी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के साथ बहुत अच्छी लगेगी।

नारियल वाली सेब की चटनी

नारियल वाली सेब की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले नारियल को कदूकस कर लें और सेब को काट लें। उसमें बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और करी पत्ता मिलाएं। अब इस मिश्रण में नमक, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी सामग्रियां ठीक से पक जाएं। ये सभी चटनियां आपको जरूर पसंद आएंगी और सेहत के लिए भी अच्छी होंगी।

सेब की मिर्ची वाली चटनी

सेब की मिर्ची वाली चटनी बनाने के लिए सेब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। इसे पैन में डालें और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और अदरक भी भूनें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि सब्जियां नरम न हो जाएं। इसमें नमक, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक और पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। यह चटनी खान-पान में तीखा स्वाद जोड़ देगी।

वजन घटाने के लिए कोशिशें की, फिर भी नहीं हुआ कुछ? हो सकती हैं ये गलतियां

वजन घटाने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन हर बार सफल नहीं हो पाते। अगर बार-बार खानपान में बदलाव और व्यायाम करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कुछ गलतियां हो सकती हैं। अक्सर लोग बिना सोचे-समझे वजन घटाने के लिए कई चीजें आजमा लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से अपनाए गए ये तरीके और गलतियां वजन घटाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानें।

पानी का कम सेवन

वजन घटाने के लिए खानपान में बदलाव के साथ-साथ पानी का भरपूर सेवन करना भी जरूरी है। पानी पाचन को ठीक रखने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद कर सकता है।

इसके अलावा पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर भी वजन घटाने में मदद कर सकता है।

लाभ के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। इसके साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी और फलों का रस भी पिएं।

पर्याप्त नींद न लेना

अगर आप वजन घटाने के लिए काफी मेहनत करने के बावजूद वजन नहीं घटा पा रहे हैं तो इसका कारण पर्याप्त नींद न लेना हो सकता है।

दरअसल, अगर आप रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है।

इसके अलावा नींद की कमी से तनाव और थकान जैसी कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वजन घटाने के लिए पूरी नींद लेना जरूरी है।

सुबह का नाश्ता छोड़ना

अगर आप वजन घटाने के चक्कर में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

सुबह का नाश्ता न छोड़ें क्योंकि यह दिन का सबसे अहम और पहला भोजन होता है। सुबह का नाश्ता न करने से शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और इससे वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो इससे शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है।

ज्यादा शारीरिक गतिविधि न करना

अगर आप वजन घटाने के लिए खानपान में बदलाव के साथ-साथ व्यायाम को भी शामिल नहीं कर रहे हैं तो आपका वजन नहीं घट सकता।

अगर आप वजन घटाने के लिए खानपान में बदलाव के साथ-साथ व्यायाम को शामिल नहीं करते हैं तो आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता। रोजाना कम से कम आधा घंटा किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करना जरूरी है।

इसके अलावा आप चाहें तो योग और टहलने को भी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

तनाव लेना

तनाव लेने से न केवल वजन बढ़ता है, बल्कि इससे कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में वजन घटाने के लिए तनाव से दूर रहना जरूरी है।

तनाव से दूर रहने के लिए आप ध्यान और गहरी सांस लेने की प्रक्रिया को अपना सकते हैं।

इसके अलावा आप चाहें तो अपनी पसंदीदा गतिविधि या फिर अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। इससे आपका मन हल्का होगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे।

भारत में बढ़ेगा एनआरआई डिपॉजिट का प्रवाह, वर्ष 27 में जमा वृद्धि 15% तक पहुंचने की उम्मीद

देश में गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) और एफसीएनआर-बी इनफ्लो से बैंक डिपॉजिट की वृद्धि दर वित्त वर्ष 27 में 15 प्रतिशत पहुंच सकती है। हालांकि, इस दौरान क्रेडिट वृद्धि दर भी मजबूत रहेगी। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया कि अभी तक एफसीएनआर-बी डिपॉजिट के जरिए अब तक करीब 13-14 अरब डॉलर जुटाए जा चुके हैं, जिससे चालू वित्त वर्ष में देश के बैंकों का डिपॉजिट आधार मजबूत हुआ है।

हालांकि, इस दौरान की वित्त वर्ष 23 से जारी ट्रेंड के मुताबिक क्रेडिट वृद्धि दर डिपॉजिट से अधिक रहेगी।

30 जून को खत्म हुए पखवाड़े में, बैंक क्रेडिट में सालाना आधार पर 18.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल डिपॉजिट राशि में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे क्रेडिट-डिपॉजिट का अंतर बढ़कर 5.3 प्रतिशत अंक हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, यह लगातार बना हुआ अंतर कोविड-19 महामारी के बाद जमा राशि जुटाने और क्रेडिट की मांग में आए संरचनात्मक बदलावों को दर्शाता है, न कि लिक्विडिटी के अस्थायी असंतुलन को।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े महानगरों में पारंपरिक जमा बाजार अब सैचुरेटेड हो चुके हैं, और जमा राशि में वृद्धि अब अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ रही है। ऐसा परिवारों की बढ़ती आय, महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के कारण हो रहा है।

साथ ही, शहरी परिवार अपनी बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी जैसे मार्केट-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हैं, जिससे बैंकिंग सिस्टम में परिवारों की जमा राशि का हिस्सा कम हो रहा है।

कर्ज देने के मामले में, रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटरी उपायों से बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन पर रोक लगने के बाद क्रेडिट ग्रोथ का दायरा बढ़ा है।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (एससीएलजीएस) के सपोर्ट से, नया कर्ज देने का रुझान इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल लोन और सोने के गहनों के बदले लोन की ओर बढ़ा है।

एसबीआई रिसर्च ने यह भी कहा कि आपूर्ति पक्ष के झटकों (जैसे कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव) का असर जमा राशि की तुलना में क्रेडिट ग्रोथ पर अधिक पड़ता है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में लगातार लिक्विडिटी की कमी बनी रहती है।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंक अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड हैं, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी मजबूत है और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) कम हैं, जिससे यह सेक्टर 'गोल्डीलॉक्सÓ (संतुलित और अच्छी) स्थिति में है।

रिपोर्ट के मुताबिक, खपत की मांग और कैपिटल खर्च के सपोर्ट से क्रेडिट ग्रोथ के अच्छे बने रहने की उम्मीद है, जबकि बैंकों के बैलेंस-शीट अनुशासन बनाए रखने की संभावना है।

लाखों निवेशकों ने एसआईपी में पैसा लगाना किया बंद, आखिर किस बात का है डर?

पिछले कुछ सालों में एसआईपी निवेश के लिए सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प के रुप में उभरा है, लेकिन ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि अब बड़ी संख्या में लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर निवेशकों का भरोसा क्यों डगमगा रहा है।

पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका बन गया है। हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम लगाकर बड़ा फंड बनाने की इसकी सुविधा ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बड़ी संख्या में निवेशक अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग इस लोकप्रिय निवेश साधन से दूरी बना रहे हैं? आइए समझते हैं

सितंबर में बंद हुईं 44 लाख से ज्यादा एसआईपीs

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 में करीब 44.03 लाख SIPs बंद हुईं। अगस्त में यह संख्या 41.15 लाख थी, यानी करीब 7% की बढ़ोतरी। पिछले साल इसी महीने में 40 लाख के आसपास SIP बंद हुई थीं। यह ट्रेंड बताता है कि निवेशक अब अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार कर रहे हैं, कुछ लोग बाजार की अस्थिरता से घबरा रहे हैं, तो कुछ अपने लक्ष्यों के पूरे होने या फंड के खराब प्रदर्शन के कारण SIP रोक रहे हैं।

चार महीने से दिख रहा उतार-चढ़ाव

AMFI के आंकड़े बताते हैं कि SIP बंद होने की रफ्तार पिछले कुछ महीनों से लगातार बदल रही है। जून में 48 लाख SIP बंद हुईं, जुलाई में 43 लाख, अगस्त में 41 लाख और सितंबर में फिर बढ़कर 44 लाख हो गईं। यह स्पष्ट है कि निवेशक अभी भी अपने निवेश को लेकर असमंजस में हैं और लगातार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कर रहे हैं।

एसआईपी बंद करने के पीछे बड़ी वजहें

पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना: कई निवेशक एक ही SIP की बजाय अपने निवेश को कई छोटे SIPs में बांटकर जोखिम घटाना और बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पुरानी SIP रोककर नई रणनीति अपनानी पड़ती है।

गलत फंड का चुनाव: कभी-कभी निवेशक बाद में समझते हैं कि उन्होंने ऐसा फंड चुना जो उनके लक्ष्य या रिस्क प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। ऐसे में एसआईपी रोकना और Systematic Transfer Plan (STP) के जरिए पैसे को बेहतर फंड में शिफ्ट करना सही कदम होता है।

सेक्टर फंड का खराब प्रदर्शन: अगर किसी सेक्टर-आधारित फंड का प्रदर्शन लंबे समय से कमजोर है, तो उसमें SIP जारी रखना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में निवेशक ब्रॉड मार्केट या लार्ज कैप फंड में जाना पसंद करते हैं।

आर्थिक दबाव या इमरजेंसी: नौकरी छूटना, मेडिकल खर्च या पारिवारिक वित्तीय संकट जैसी स्थितियों में SIP रोकना मजबूरी बन जाता है। इस समय नकदी बनाए रखना प्राथमिकता होती है।

एसआईपी रोकना हमेशा गलती नहीं

अक्सर कहा जाता है कि SIP कभी बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञ इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि SIP रोकना जरूरी नहीं कि खराब फैसला हो बस यह फैसला जरूरत और सलाह पर आधारित लेना चाहिए।

100 साल पुराने कानून का पहली बार इस्तेमाल, ट्रंप ने कनाडा पर लगाया 50% टैरिफ

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कनाडा अमेरिकी कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ भेदभाव कर रहा है। इस फैसले से अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार विवाद और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप ने यह फैसला 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 (Section 338) के तहत लिया है। यह कानून राष्ट्रपति को उन देशों पर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, जो अमेरिकी सामान के साथ भेदभाव करते हैं। खास बात यह है कि करीब 100 साल पुराने इस कानून का पहली बार इस्तेमाल किया गया है।

यह नया टैरिफ 30 दिन बाद यानी 19 अगस्त से लागू होगा। इसका असर वाइन, सीमेंट, आइस हॉकी का सामान, डेयरी उत्पाद, स्विमिंग पूल, फर्नीचर, मछली पकड़ने वाली रॉड, बीज, कपड़े, विग और कई दूसरे सामानों पर पड़ेगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ निष्पक्ष और बराबरी वाले समझौते करना चाहता है। लेकिन कनाडा अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए टैरिफ का जवाब लगातार जवाबी कार्रवाई से दे रहा है।

वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार ने व्यापार विवाद खत्म करने के लिए अमेरिका को कई प्रस्ताव दिए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप द्वारा पहले लगाए गए टैरिफ अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते (USMCA) का उल्लंघन थे। कार्नी ने कहा कि कनाडा ने केवल उन्हीं अमेरिकी ऑटो टैरिफ का जवाब दिया, जो इस समझौते के खिलाफ थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यापार विवाद से दोनों देशों के लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ा है और कनाडा बातचीत के लिए तैयार है।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कनाडा और चीन ने पहले भी अमेरिकी टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाए थे। इसी वजह से अमेरिका और मेक्सिको के बीच चल रही USMCA से जुड़ी बातचीत में कनाडा को शामिल नहीं किया गया। जेमिसन ग्रीर इस समय मेक्सिको सिटी में मेक्सिको के साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं।

जंगलों की आग पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी

रविवार को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ट्रंप और कार्नी की मुलाकात हुई थी। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा से जंगलों में लगी आग पर काबू पाने को कहा, क्योंकि उसका धुआं अमेरिका के कई हिस्सों तक पहुंच रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि इस प्रदूषण से अमेरिका को होने वाले बेहिसाब खर्च को भी कनाडा पर लगाए गए टैरिफ में शामिल किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कनाडा का डेयरी सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए नुकसानदायक है। साथ ही कनाडा अमेरिका से आने वाली कारों पर टैरिफ और आयात सीमा (कोटा) लगाता है, जबकि कुछ दूसरे देशों को ऐसी छूट देता है। अमेरिका का दावा है कि पिछले एक साल में कनाडा ने अमेरिकी कारों का आयात 22% और अमेरिकी शराब का आयात 81% कम कर दिया है। कई कनाडाई प्रांतों ने अमेरिकी शराब की बिक्री भी रोक दी है। हालांकि ट्रंप ने ऊर्जा, पोटाश, मछली, क्रिटिकल मिनरल्स और पहले से सेक्शन 232 के तहत आने वाले कुछ उत्पादों को इस नए टैरिफ से बाहर रखा है।

अमेरिका ने ईरान पर फिर शुरू की बमबारी, कई इलाकों में धमाके

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने देर रात कहा कि वह होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की कोशिश में ईरान पर लगातार 10वीं रात हमले कर रही है। ये नए हमले एक और अमेरिकी सैनिक की मौत और ईरान द्वारा अमेरिका के सहयोगी देशों कुवैत, जॉर्डन और बहरीन (जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है) पर हमले करने के बाद हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये ताज़ा हमले उस ईरानी सैन्य क्षमता को और कम करने के लिए किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। हालांकि अमेरिका और ईरान फिर से पूर्ण युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर उम्मीद की किरण भी दिखी है, क्योंकि ईरान के गृह मंत्री बातचीत के लिए पाकिस्तान गए हैं, जो इस संघर्ष में एक अहम मध्यस्थ है। पिछले महीने लड़ाई खत्म करने के लिए किया गया अंतरिम समझौता टूट गया है। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही काफी हद तक रुक गई है। और जैसे-जैसे लड़ाई तेज हो रही है, दोनों पक्षों ने आम नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिस पर लाखों लोग निर्भर हैं।

सोमवार को वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक नया संभावित खतरा तब सामने आया जब यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों ने कहा कि वे सऊदी अरब को लाल सागर (Red Sea) में जहाज भेजने से रोकने की योजना बना रहे हैं। यह युद्ध के दौरान तेल निर्यात का एक वैकल्पिक रास्ता है। हाल के हफ्तों में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। सोमवार को बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था और अमेरिका में आम गैसोलीन की कीमत औसतन $4 प्रति गैलन तक पहुंच गई।

FBI की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में एक और भारतीय, कौन है हरमनवीर सिंह जिसे तलाश रहा अमेरिका

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की फेडरल जांच एजेंसी FBI ने एक और भारतीय नागरिक हरमनवीर सिंह को अपनी मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि हरमनवीर एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। FBI के मुताबिक हरमनवीर सिंह पर कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी करने, उनकी सप्लाई की साजिश रचने और उन्हें दूसरे देशों तक पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहा है।

अमेरिकी फेडरल एजेंसी FBI के अनुसार हरमनवीर कथित तौर पर 'रविंदर ढांडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप' से जुड़ा हुआ है। यह गिरोह कनाडा के वैंकूवर से चलाया जा रहा है। गैंग पर आरोप है कि यह नेटवर्क अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में सक्रिय ड्रग्स तस्करों तक बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथामफेटामाइन पहुंचाता था।

जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर अमेरिका की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने पिछले महीने 23 जून को हरमनवीर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उस पर ड्रग्स की तस्करी की साजिश, नशीले पदार्थों के निर्यात की साजिश और बिक्री के इरादे से ड्रग्स रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

FBI ने दावा करते हुए बताया कि हरमनवीर, हरी गौतम और हरमन संधू जैसे कई नाम से भी पहचान छिपाकर काम करता था। एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 26 सितंबर 1994 है। वह भारतीय नागरिक है, उसकी लंबाई करीब 5 फीट 7 इंच है जबकि उसका वजन करीब 190 पाउंड है। उसके बाल और आंखें काले रंग की हैं। लोगों से अपील करते हुए FBI ने कहा कि अगर किसी के पास हरमनवीर सिंह के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी हो तो वह तुरंत जांच एजेंसी के नजदीकी कार्यालय, अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें। यह जानकारी ऑनलाइन माध्यम से या गुप्त रूप से भी दी जा सकती है।

इस पूरे मामले की जांच FBI के लॉस एंजिलिस फील्ड ऑफिस की टीम कर रही है। एजेंसी का कहना है कि हरमनवीर की गिरफ्तारी से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।

नहीं माना तो फिर दहलेगा ईरान! अमेरिका ने लगातार 10वें दिन बमबारी करने के बाद दी चेतावनी

वॉशिंगटन, एजेंसी। होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगातार 10वीं रात हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य ताकतों को कमजोर करना है, जिनके जरिए वह होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि 20 जुलाई को रात 9 बजे (अमेरिकी समय) एक और हवाई अभियान पूरा किया गया। इस दौरान ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, नौसैनिक ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट तथा एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।

अमेरिका का कहना है कि इन हमलों से ईरान की हमला करने की क्षमता कम होगी और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा बढ़ेगी। CENTCOM के मुताबिक, मई की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना ने करीब 900 व्यापारिक जहाजों और 45 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सुरक्षित आवाजाही में मदद की है। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसके सैनिक पूरी तरह तैयार हैं और अगर ईरान ने नागरिक जहाजों पर हमला जारी रखा तो उसे इसका जवाब दिया जाएगा।

लगातार 10 रात तक हवाई हमले करने के बाद भी ईरान ने होर्मुज पर अपना दबाव कम नहीं किया है। मंगलवार तड़के ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज के क्रू मेंबर्स को अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़ना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच ईरान के गृह मंत्री बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कोई नया समझौता हो पाएगा या नहीं। पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुआ अंतरिम समझौता अब लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद लड़ाई फिर तेज हो गई है। दोनों पक्ष अब ऐसे ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं, जिनका इस्तेमाल लाखों आम लोग करते हैं। इससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

इस तनाव का असर तेल बाजार पर भी पड़ा है। ब्रेंट क्रूड का भाव 88 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4 डॉलर प्रति गैलन हो गई है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है और अमेरिका में इस साल होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है।

विदेश मंत्रालय ने रूसी राजनयिक को किया तलब, जहाज पर हमले की निंदा की, चार भारतीयों की मौत पर क्या कहा?

नई दिल्ली, एजेंसी। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले के बाद विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मंगलवार को रूस के प्रभारी राजदूत को तलब किया। इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 19 जुलाई की शाम को एमवी गोल्डन लियो नाम के जहाज पर हमला हुआ। उस समय जहाज ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहा था। घटना के समय जहाज पर चालक दल के कुल 17 सदस्य मौजूद थे, जिनमें पांच भारतीय नागरिक शामिल थे।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की। एमईए ने कहा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार चार भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो गई है, जबकि एक भारतीय नागरिक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूक्रेन में हमारा मिशन स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद देने के लिए प्रयास कर रहा है। हम मृत भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल भारतीय नागरिक के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

मंत्रालय ने आगे कहा, भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और दोहराता है कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में डालना या समुद्री आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए।

मिसाइल हमले में कितने लोगों की मौत हुई?

कीव पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस की ओर से दागी गई मिसाइल तुर्किये के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज गोल्डन लियो से टकराई। इस हमले में कुल 10 लोगों की मौत हुई।

यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूसी सेना ने तीन केएच-59/केएच-69 क्रूज मिसाइलें दागीं। इनमें से एक मिसाइल गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले व्यापारिक जहाज गोल्डन लियो के दाहिने हिस्से से टकराई, जिससे उसमें आग लग गई। यूक्रेन के ओडेसा में आठ नाविकों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?

रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा, पूरे दिन रूसी संघ की सशस्त्र सेनाओं ने यूक्रेनी बंदरगाहों और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के हितों में काम करने वाले जहाजों पर हमले जारी रखे। मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में जहाज रोधी ओनिक्स मिसाइलों, हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों और लक्ष्य पर मंडराकर हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जिन ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही, उनमें ओडेसा बंदरगाह के पास खड़े दो ऐसे बड़े मालवाहक जहाज भी शामिल थे, जिनमें कथित तौर पर सैन्य सामान ले जाया जा रहा था।

गाज़ियाबाद-दिल्ली रेल रूट पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे... 53 ट्रेनें प्रभावित, 16 रद्द

नई दिल्ली, एजेंसी। मंगलवार सुबह दिल्ली-NCR के व्यस्त रेल रूट पर एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। दिल्ली डिवीज़न के गाज़ियाबाद और नई दिल्ली सेक्शन के बीच एक मालगाड़ी के छह डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे के चलते गाज़ियाबाद-दिल्ली रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने या चोटिल होने की खबर नहीं है। घटना के बाद, डिवीज़नल रेलवे मैनेजर और एडिशनल डिवीज़नल रेलवे मैनेजर समेत रेलवे के सीनियर अधिकारी हालात का जायज़ा लेने के लिए मौके पर पहुँचे। ट्रैक की मरम्मत करने और पटरी से उतरे डिब्बों को हटाकर जल्द से जल्द ट्रैफिक बहाल करने के लिए रेलवे की टेक्निकल और राहत टीमों को तुरंत तैनात किया गया।

53 ट्रेनें प्रभावित

हादसे के कारण गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली और नई दिल्ली के बीच चलने वाली कई EMU लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस रुकावट से कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुईं। इंतज़ाम के तहत, 24 ट्रेनों को दिल्ली-नई दिल्ली रूट से डायवर्ट किया गया, जबकि 16 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गईं।

इसके अलावा, पाँच पैसेंजर ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गईं और आठ ट्रेनों को रेगुलेट किया गया, जिनमें मुरादाबाद डिवीज़न और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रूट से आनंद विहार जाने वाली ट्रेनें शामिल थीं।

कई पैसेंजर ट्रेनों को नई दिल्ली के बजाय गाज़ियाबाद डायवर्ट किया जा रहा है या वहाँ से डायवर्ट किया जा रहा है। सहारनपुर-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन का रूट बदल दिया गया है और इसे साहिबाबाद-दिल्ली सराय रोहिल्ला रूट से डायवर्ट किया गया है। अलीगढ़ और पलवल आने-जाने वाली ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है।

सुबह के व्यस्त समय में हुए इस हादसे के कारण, दिल्ली-NCR में काम पर आने-जाने वाले रोज़ाना यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। नॉर्दर्न रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) या अधिकृत रेलवे चैनलों के ज़रिए अपनी ट्रेनों का लेटेस्ट स्टेटस देख लें। रेलवे की टीमें प्रभावित हिस्से को साफ करने और ट्रेनों का सामान्य संचालन बहाल करने के लिए घटनास्थल पर काम कर रही हैं।

इन फिल्मों को देख राजकुमार राव की एक्टिंग के मुरीद हो जाएंगे ...

राजकुमार राव बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और वर्सटाइल अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 'शाहिद' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और 'स्त्री 2', 'न्यूटन', 'बरेली की बर्फी', और 'श्रीकांत' जैसी सुपरहिट व समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है।

राजकुमार राव की फिल्म 'भूल चूक माफ' 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में शादी में हो रही मुश्किलों को दिखाया गया है। फिल्म में राजकुमार राव की शादी होने में कई अड़चनें आती हैं। राजकुमार राव की कई फिल्में हैं जिनमें शादी के मुद्दे को दिखाया गया है। इन फिल्मों में 'शादी में जरूर आना', 'बधाई दो' और 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' शामिल हैं। इस खबर में हम आपको राजकुमार राव की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें उन्होंने दूल्हे के अलावा दूसरे किरदार निभाए हैं।

भीड़

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'भीड़' में कोरोना महामारी के बाद उपजे हालात को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी को प्रवासी श्रमिकों को सीमा पार करने से रोकने का काम सौंपा गया है। पुलिस वाला जब लोगों की पीड़ा को देखता है तो वह लोगों की मदद करने लगता है। पुलिस अफसर के किरदार को राजकुमार राव ने अच्छे से निभाया है।

छलांग

साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'छलांग' एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है। फिल्म में राजकुमार राव ने एक खेल अध्यापक की भूमिका निभाई है। फिल्म में वह एक आलसी प्रशिक्षक हैं, जो नौकरी में बने रहने के लिए न्यूनतम काम करते हैं। फिल्म में तब मजा आता है जब एक नया शिक्षक उनकी नौकरी और उनसे प्यार करने वाली महिला को छीनने की धमकी देता है। फिर राजकुमार राव एक्शन मोड में आते हैं।

न्यूटन

साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'न्यूटन' में राजकुमार राव ने रिटर्निंग अफसर का किरदार निभाया है। फिल्म में राजकुमार राव को एक ऐसे इलाके में चुनाव की ड्यूटी के लिए भेजा जाता है जो राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। राजकुमार राव अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने अच्छी आदाकारी की है। फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के अलावा कई दूसरे अवॉर्ड्स भी मिले थे।

अलीगढ़

साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'अलीगढ़' एक प्रोफेसर पर आधारित थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी अहम किरदार में थे। इस फिल्म में राजकुमार राव ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मराठी भाषा के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास रामचन्द्र सिरस पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया है कि एक प्रोफेसर जिसकी फीलिंग दूसरे लोगों से अलग थी, उन्हें कितनी दिक्कतें हुईं। फिल्म में राजकुमार राव एक सच्चे पत्रकार की भूमिका निभाते हैं।

शाहिद

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'शाहिद' एक वकील की कहानी पर आधारित थी। शाहिद आजमी जिन पर पूर्व आतंकवादी कार्यकर्ता का इल्जाम लगता है, वह बाद में एक वकील बन जाते हैं। वह उन लोगों के लिए न्याय पाने के लिए लड़ते हैं, जिन्हें आतंकवाद के झूठे आरोप में दोषी ठहराया गया है। इस किरदार को राजकुमार राव ने बखूबी निभाया है। फिल्म की खूब सराहना हुई थी।

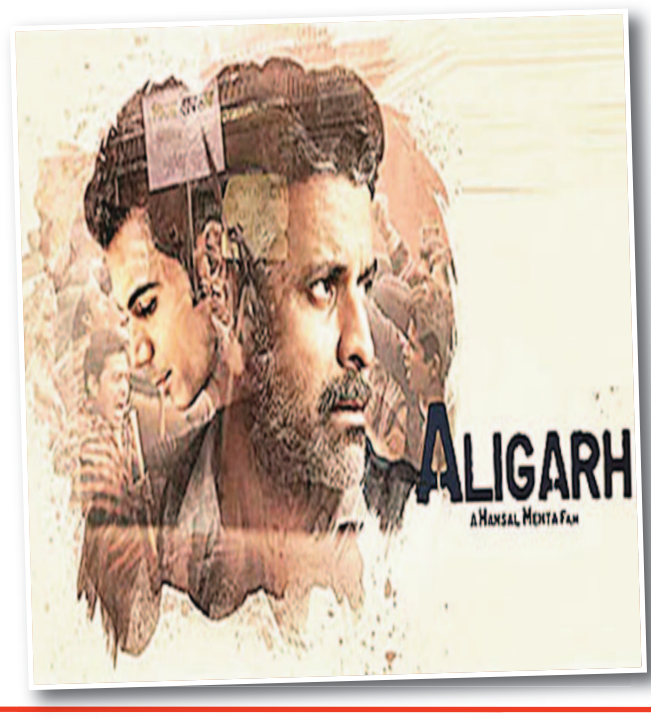

खुशाली कुमार की दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर जारी, 24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म

अभिनेत्री खुशाली कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म दुल्हनिया ले आएगी को लेकर सुर्खियों में हैं। यह एंटरटेनमेंट से भरपूर एक फैमिली ड्रामा फिल्म होगी। इसका ट्रेलर देखकर तो कुछ यही लग रहा है। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का फर्स्ट लुक पोस्टर बीते महीने रिलीज हुआ था। आज ट्रेलर सामने आया है। इसमें खुशाली कुमार के अलावा दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। ट्रेलर की शुरुआत नव्या (खुशाली कुमार) की शादी की टेंशन से होती है। बरेली की रहने वाली नव्या की उम्र 32 हो चुकी है और शादी का बहुत दबाव है।

ट्रेलर की शुरुआत ही तानों के साथ होती है, 32 की हो गई है और कितना टाइम लगेगा। मगर, नव्या पर इसका जरा भी फर्क नहीं और वह जवाब देती है, हर लड़की 31 के बाद 32 की ही होती है। जवाब मिलता है, हमारी रिश्तेदारी में कोई ऐसी लड़की नहीं है, जो 32 की है और उसकी शादी नहीं हुई। कई लड़के रिजेक्ट करने के बाद एक लड़के से शादी का बात होती है, लेकिन यहां भी राह में रोड़ा है। शादी की तैयारियों के बीच चीजें बिखर जाती हैं। मां-बाप की अलग टेंशन है। ऐसे में किराए के दूल्हे की खोज शुरू होती है।

शादी से एक दिन पहले का मंजर है, जहां मंडप सज गया है। रिश्तेदार आ रहे हैं। मगर, दूल्हे का पता नहीं है। फिल्म का ट्रेलर काफी मजेदार है। इसमें कॉमेडी भी भरपूर है और फैमिली ड्रामा भी। फिल्म का निर्देशन आकाशदित्य लामा ने किया है।

मातृभूमि से सलमान खान ने जारी किया नया गाना मेरा जी नहीं भरा, श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा ने लगाए सुर

सलमान खान की फिल्म मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस रिलीज को लेकर चर्चाओं में है। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म के विषयवस्तु पर चीन ने आपत्ति जताई है, जिसके चलते सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र मिलने में देरी हो रही है। इस बीच, फैंस के बीच उत्सुकता को बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने फिल्म से नया गाना मेरा जी नहीं भरा जारी किया है। इस गाने को जो जैन शॉ और अभिश्री सेन पर फिल्माया गया है।

सलमान खान फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जारी हुए इस गाने को श्रेया घोषाल और विशाल मिश्रा ने आवाज दी है। इसके म्यूजिक कंपोजर समीर टंडन और कुमार गौरव सिंह हैं, जबकि बोल समीर और विश्वदीप जेस्ट ने लिखे हैं।

फिल्म भारतीय सेना और चीनी सैनिक के बीच हुए गलवान घाटी के संघर्ष पर आधारित है, लेकिन कहानी के बीच पनपते खूबसूरत प्यार को गाने के जरिए बखूबी पेश किया है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी मुख्य किरदार में हैं।

फिल्म मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस को अगस्त में रिलीज किया जाना था। अब लगता है कि फैंस को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी रिलीज के आसार इस साल तो दूर-दूर तक नहीं दिख रहे हैं। ताजा अपडेट है कि फिल्म को रिलीज करने की हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन यह इस साल तक टल सकती है। बता दें, फिल्म मातृभूमि का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com